

अमृतपाल सिंह के कितने करीब पहुंची पुलिस! बड़ा सुराग लगा हथ, 2 और करीबी हुए गिरफ्तार

मोहाली। खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह पिछले एक महीने से पुलिस और खुफिया तंत्र को छका रहा है। उसके लगभग सभी साथियों पर शिकंजा कस चुका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस अमृतपाल के काफी करीब है। इस बीच सोमवार रात को मोहाली में दबिश डालकर पंजाब और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर अमृतपाल को छिपाने और भागने में मदद करने का आरोप है। पंजाब और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान में सोमवार रात मोहाली के सेक्टर 88 स्थित एक घर से दो घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद गुरुजट सिंह और निशा रानी को गिरफ्तार किया। सूत्रों ने कहा कि दोनों पर अमृतपाल सिंह को भागने में मदद करने का आरोप है। इन्होंने अमृतपाल को अन्य सहायता भी प्रदान की। हालांकि, पुलिस ऑपरेशन के बारे में चुपचाप सांभ रही और इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। 18 मार्च से अमृतपाल के खिलाफ चल रहे मेगा ऑपरेशन के दौरान दो दिन पहले, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के एक प्रमुख सहयोगी को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आश्रय और अन्य सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस उप महानिरीक्षक (सीमा रेंज) नरिंदर भागव ने संवाददाताओं को बताया कि लुधियाना निवासी और पीलीभीत में एक डेरा के प्रभारी जोगा सिंह को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से गिरफ्तार किया गया था, जब वह हरियाणा से पंजाब आया था। अमृतपाल तक पहुंचाई गाड़ी जोगा सिंह ने अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगी पापलप्रोत सिंह को पीलीभीत में आश्रय दिया और उनके लिए वाहनों की व्यवस्था भी की। अमृतपाल और उसका करीबी पापलप्रोत सिंह, जो अब पुलिस की गिरफ्तार में हैं, 18 मार्च को पुलिस की कार्रवाई के बाद पंजाब से भाग गया था। वह 28 मार्च को राज्य लौटे।

विरोध में धुआं निकाल देता हूं, गहलोत पर बरसते हुए पायलट का समझौते से इनकार

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आंतरिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा मनमुटाव हर दिन नए स्तर पर पहुंचता जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आंतरिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा मनमुटाव हर दिन नए स्तर पर पहुंचता जा रहा है। चुनाव से पहले आर-पार के मूड में दिख रहे सचिन पायलट ने अब कहा है कि वह ऐसा विरोध करते हैं कि धुआं निकाल देते हैं। एक बार फिर वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते हुए पायलट ने कहा कि जिन भाषणों के आधार पर चुनाव में जीत हासिल की थी उस पर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपने संस्कारों की वजह से उन्होंने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। एक कार्यक्रम में पायलट ने कहा, बहुत से मामलों की जांच चल रही है उनका मैं स्वागत करता हूं। जो जनता की

जब पर डाका डालेगा उसकी जांच करो। जेल में डालो, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ भाषण देकर, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर हमने वोट लिया था, वह वादा भी पूरा करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पायलट लगातार वसुंधरा सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हाल ही में एक दिन का अनशन भी किया था, जिससे पार्टी में काफी हलचल है। इस बीच उन्होंने कहा, मैंने कभी मर्यादाओं को लांघा नहीं। अपने शब्दों, भाषणों में, हो सकता है गुद्वा जी कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी स्लिप नहीं होता। क्योंकि संस्कार ऐसे हैं मेरे बचपन से। शालीनता, विनम्रता, मान-सम्मान, आदर, प्रेम-भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान हमेशा किया,



विरोध भी करता हूँ तो ऐसा कि धुआं निकालता हूँ लेकिन भाषा का संयम नहीं खोता। क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल गया वह कभी वापस नहीं होता है। पायलट ने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कि पायलट ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपने मुद्दों से समझौता नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा, हम जेलों में गए, धरने दिए, भूख हड़ताल की है, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थीं, मेरे ऊपर मैं बड़ी हूँ। लेकिन राजनीति में जब टकराव होता था तो बराबर का होता था। लेकिन ओच्छी भाषा का इस्तेमाल ना तो पहले किया और ना करने वाले हैं। लेकिन मुझे सिद्धांतों को लेकर, जुबान से किए वादों को लेकर ना पहले कभी समझौता किया और ना आगे कभी समझौता करूँगे।

दिल्ली और महाराष्ट्र में आने वाला है सियासी भूचाल? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने दिए बड़े संकेत

मुंबई। देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी विस्फोट होने वाला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यह दावा कर रही हैं। हालांकि, उन्हें इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। खास बात है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव के संकेत दे रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुले का कहना है कि पहला धमाका दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होने जा रहा है। हालांकि, उन्होंने इस दौरान एक बात साफ कर दी है कि अजित किसी बात से नाराज नहीं हैं। खास बात है कि राज्यसभा सांसद संजय राज ने सीनियर पवार से मुलाकात के बाद संकेत दिए थे कि कुछ राकंपा विधायक दबाव में पार्टी छोड़ सकते हैं। खबरें ये भी थीं कि अजित और शरद दोनों ही राकंपा विधायकों के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अब तक पार्टी और दोनों नेताओं की ओर से ताजा सियासी घटनाक्रम को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अजित के पते को लेकर पूछे सवाल पर सुले ने कहा, आप सभी चैनल वाले एक यूट्यूब अजित दादा के पीछे लगा लें। प्रदेश में कई समस्याएँ हैं, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है। एक कार्यक्रम रद्द होने से कुछ नहीं होगा। भाजपा में



शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, यह बात दादा से पूछिये। मेरे पास गाँसिप का वक्त नहीं है...। सोमवार को राकंपा के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अजित भाजपा में शामिल होंगे। एसी रिपोर्ट्स का कोई आधार नहीं है। नागपुर में एमवीए रैली के दौरान मैं और अजित साथ थे। मेरे विचार से अभी तो शिंदे-फडणवीस सरकार के पास बहुत है, उन्हें सरकार की स्थिरता के लिए और विधायकों की जरूरत नहीं है।

हरियाणा के करनाल में राइस मिल ढहने से 4 की मौत

अभी कड़ियों के दबे होने की आशंका

करनाल। हरियाणा के करनाल में देर रात एक राइस मिल ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घटना जिस वक्त हुई, उस दरम्यान 200 मजदूर मिल में सो रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, अभी भी कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद दमकल की गाड़ियाँ मौके पर हैं और बचाव अभियान जारी है। घटना करनाल के तरावड़ी स्थित तीन मंजिला मिल में हुई। हरियाणा के करनाल में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी



रात एक राइस मिल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना करनाल के तरावड़ी स्थित तीन मंजिला मिल में हुई। शिव शक्ति राइस मिल में सोए कुछ मजदूरों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। करनाल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने पुष्टि की है कि चार मजदूरों की मौत हो गई है और उनके शव निकाल लिए गए हैं और लगभग 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

है और अधिकारियों ने कहा कि मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। एस्पसी ने कहा कि बचाव कार्य जारी है और अभी और मौतों की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। मजदूरों ने बताया कि यह घटना मंगलवार तड़के तीन बजे हुई जब शिव शक्ति राइस मिल में करीब 200 मजदूर सो रहे थे तभी ऊपर की मंजिला की छत गिर गयी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया।

घर से अचानक लापता हो गए हैं मुकुल राय, रहस्य गहराया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नेता मुकुल राय अचानक घर से लापता हो गए हैं। वह कई दिनों से बीमार हैं और कई चीजें भूल जा रहे हैं। उनके बेटे और पूर्व विधायक शुभांशु राय ने इस संबंध में पुलिस से संपर्क साधा है। उन्होंने बताया है कि सोमवार से सॉल्टलेक स्थित घर से वह लापता हुए हैं। शुभांशु राय ने उत्तर 24 परना के अपने आवासीय क्षेत्र बीजपुर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट थाने में भी इसी शिकायत की प्रती जमा दी है। शुभांशु ने दावा किया है कि दो लोग आए और मुकुल को अपने साथ ले गए हैं। उसके बाद से पिता की कोई खबर नहीं मिल रही। इधर एक फ्लाइंग टिकट सामने आया है जिसमें मुकुल राय का नाम है। पता चला है कि कृष्णानगर उत्तर से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी की उपस्थिति में तुण्मूल में वापसी करने वाले मुकुल सोमवार रात दिल्ली गए

हैं। किस वजह से उन्होंने दिल्ली की यात्रा की है इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उनके फोन पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, न ही उनके बेटे से किसी तरह की कोई बात हो पाई है। बताया जा रहा है कि वह अपनी मर्जी से दिल्ली गए हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में उनके बेटे का नाम सामने आने के बाद वे बेचैन थे और संभवतः उसी के चलते वे दिल्ली गए हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि चिकित्सा कारणों से वे दिल्ली गए होंगे। पुलिस ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों ने बताया है कि मुकुल के दिल्ली जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि एक दौर में ममता के बेहद खास रहे मुकुल राय ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद पांच सालों तक ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर पर मुखर तरीके से हमलावर थे।

अप्रैल में ही जून-जुलाई जैसा हाल, झुलसाने वाली गर्मी से दिल्ली को कब मिलेगी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी ने अप्रैल में ही जून-जुलाई जैसा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों को कल से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से दिल्ली में बुधवार से कुछ राहत के आसार जताए गए हैं। वहीं, आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार से गुरुवार के बीच राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में भी कमी आने की संभावना है।



सबसे गर्म दिन रहा। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य है। इससे पूर्व बीते शनिवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया था। मंगलवार को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बता दें कि, मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्रप्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना को देखते हुए ऑरिज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी दी है। आईएमडी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार में गंगा के मैदानी हिस्से में लगातार चार दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भी अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। 18 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है।

20 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण

नई दिल्ली। साल का पहला सूर्यग्रहण गुरुवार को लगने जा रहा है। यह संयोग वैशाख अमावस्या के दिन बन रहा है। मालूम हो कि यह सूर्यग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। हालांकि भारत में यह दिखाई नहीं देगा। 2023 में कुल चार ग्रहण लगेगे, जिसमें से दो सूर्यग्रहण और दो चंद्र ग्रहण होंगे। 20 अप्रैल को वैशाखी अमावस्या के दिन लगने वाला सूर्यग्रहण हाईब्रिड यानी संकर सूर्यग्रहण होगा। सुबह सात बजकर चार मिनट पर लगेगा सूर्यग्रहण

साल का पहला सूर्यग्रहण सुबह 7:04 से शुरू होगा और दोपहरा 12:29 बजे तक समाप्त हो जाएगा। भारतीय ज्योतिषीय कैलेंडर के मुताबिक, यह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्यग्रहण ऑस्ट्रेलिया, पूर्व और दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। इसके अलावा पूर्वी तिमोर के पूर्वी भागों में व डार्व द्वीप में यह ग्रहण नजर आने वाला है। अंत में इंडोनेशिया में पापुआ प्रांत के कुछ ही हिस्सों में यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण नजर आएगा। मालूम हो कि इस सूर्यग्रहण के ठीक 15 दिनों के बाद चंद्रग्रहण लगेगा, जबकि दूसरा सूर्यग्रहण 14 अक्टूबर को होगा।



मालूम हो कि इस ग्रहण का पाथ संकरा होने के कारण इसे संकर ग्रहण कहा जाता है। जिस कारण इसे दुर्लभ भी माना जाता है।

अंत में इंडोनेशिया में पापुआ प्रांत के कुछ ही हिस्सों में यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण नजर आएगा। मालूम हो कि इस सूर्यग्रहण के ठीक 15 दिनों के बाद चंद्रग्रहण लगेगा, जबकि दूसरा सूर्यग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। सुंदर होता है। हाईब्रिड सूर्य ग्रहण में पृथ्वी की घुमावदार सतह के चलते कभी-कभी ग्रहण वलयाकार और पूर्ण के बीच स्थानांतरित हो जाता है।

संपादकीय

शराब के खिलाफ

बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत होने पर पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का एलान स्वामत-योग्य होने के साथ ही विचारणीय भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को यह घोषणा की है और ऐसी मांग पहले से होती आई है। हालांकि, इसके पहले खुद मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा था कि शराब पीकर मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, पीओगे, तो मरोगे। नैतिकता संबंधी प्रश्न भी उठे थे कि गलत काम के लिए मुआवजा क्यों दिया जाए, लेकिन अब सरकार का जो नया कल्याणकारी रूप सामने आया है, उसके अनेक सकारात्मक निहितार्थ हैं। हालांकि, यहां भी शराबबंदी के प्रति नीतीश कुमार की दृढ़ता और मंशा स्पष्ट है। यह मुआवजा आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए मृतक के परिजनों को एक तरह से संकल्प या शपथ लेने की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि चार लाख रुपये दिए जाएंगे, मगर मृतक के परिजनों को यह लिखकर देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी। उसने कहा कि शराब पी थी, उसका नाम और पता भी देना होगा। साथ ही, उसे यह भी लिखना होगा कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। हम इसका समर्थन करते हैं। भविष्य में परिवार का कोई सदस्य शराब नहीं पीएगा। मुआवजे के लिए रखी गई विस्तृत शर्त कारगर और प्रशंसनीय है। इससे बिहार में शराब माफिया पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। इस मुआवजे को एक तरह से अपराध के खिलाफ उपाय या प्रोत्साहन योजना के रूप में देखा जा सकता है, इसकी जरूरत पहले से ही रही है। खास बात यह है कि मुआवजा केवल ताजा मामलों में ही नहीं, बल्कि शराब से हुई मौतों के पुराने मामलों में भी दिया जाएगा। मतलब, जो शराब माफिया पहले बंद गए हैं, उनकी भी अब खैर नहीं। हां, इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि पुलिस को ऐसे लोगों की सुरक्षा का प्रबंध भी करना होगा, जो अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे। पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है। पुलिस-प्रशासन को शराब के खिलाफ पूरे समाज को साथ लेकर चलना होगा, तभी अपराधियों को घेरना संभव होगा। अफसोस, पुलिस का रवैया लोगों के साथ पहले से ही दोस्ताना रहता, तो सरकार को यूं मुआवजा या अपराध विरोधी प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई थी, पर शराबखोरी रुकी नहीं है। राज्य में सैकड़ों लोगों की जान गई है, क्योंकि उन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया। ताजा हादसे में मोतिहारी में कई सारे लोगों की मौत हुई है और पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें संदेह नहीं है कि दिखावे की कार्रवाई से आगे बढ़कर पुलिस को काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अगर शराबबंदी के लिए अपने कड़े रुख को बदलते हुए लचीलापन दिखाया है, तो शासन-प्रशासन को एकजुट होकर बिहार को शराब मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस को अपना ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए कि राज्य में कहीं भी शराब बनाने-बेचने-पीने की कोई हिम्मत न कर सके। पुलिस को सफल कार्रवाई व आम लोगों को कारगर सूचना देने के लिए प्रसूकृत किया जाना चाहिए। अपने-अपने क्षेत्र में रसूखदार समाजसेवियों व राजनेताओं को भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। शराब कारोबार पर पंचायतों के जरिये अंकुश संभव है, मगर इसके लिए कारगर योजना और निर्देश की जरूरत है। बिहार में शराब विरोधी बड़े सामाजिक अभियान की जरूरत बहुत बढ़ गई है।

आज का राशीफल

मेष	व्यावसायिक समस्या सुलझाने में आप सफल होंगे। रक्तचाप या हृदय रोगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। टकराव की स्थिति आपके हित में न होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं।
वृषभ	पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अंधलासा पूरी होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
मिथुन	आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।
कर्क	राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खानपान में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे।
सिंह	पिता या उच्चधिकारी का सहयोग मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।
कन्या	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन लाभ होगा। रुपए जैसे के लेन देन में सावधानी रखें। वाणी की सौम्यता आवश्यक है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।
तुला	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। किसी अधिभ्रम मित्र से मिलना होगा। धन हानि की संभावना है।
वृश्चिक	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशावादी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। विरोधियों का पराभव होगा।
धनु	आर्थिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। जारी प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा।
मकर	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।
कुम्भ	गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।
मीन	व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। उदर चिकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

विचार मंथन

(लेखक-सनत जैन)

भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार जेल में 77 फीसदी विचाराधीन कैदी बंद है। इनमें से 68 फीसदी विचाराधीन कैदी अनपढ़ और आठवीं मिडिल स्कूल से कम पास हैं। यह कैदी दलित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं। इन कैदियों में 20 फीसदी कैदी मुसलमान हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षमता से अधिक कैदियों के जेल में होने के कारण, इनके मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वहीं इनके संवैधानिक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हर चार में से तीन कैदी विचाराधीन हैं। इनके पास जमानत के लिए नाहि संपत्ति होती है, और ना ही पैसे होते हैं। जिसके कारण यह छोटे-मोटे अपराधों में एक बार

जेल जाते हैं। जमानत के अभाव में वर्षों इन्हें जेल में बंद रखा जाता है। इनकी आर्थिक दृष्टि ऐसी नहीं होती है, कि यह अपना मुकदमा भी लड़ सकें। परिवारजन उन्हें आर्थिक संकट के चलते भी बंधोसे छोड़ देते हैं। 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था, कि 80 फीसदी कैदियों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जेलों में बंद रखा गया। 2021 में रिहा किए गए 95 फीसदी विचाराधीन कैदियों को न्यायालय ने जमानत भी दी। लेकिन जमानत राशि नहीं भर पाने के कारण यह जेलों में बंद है। भारत के 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता से अधिक कैदी पिछले कई वर्षों से बंद है। इसमें सबसे ज्यादा बिहार की हालत खराब है। जहां 140 फीसदी से अधिक कैदी हैं। उत्तराखंड में 185 फीसदी क्षमता से अधिक कैदी बंद है। रिपोर्ट के अनुसार 391 जिलों में, क्षमता की तुलना में 150 फीसदी तथा 709 जिलों में 100 फीसदी से अधिक कैदी बंद हैं। आदर्श

कारावास नियमावली के अनुसार 200 कैदियों पर एक सुधारात्मक अधिकारी और 500 कैदियों पर एक मनोचिकित्सक होना अनिवार्य है। जेलों में 2770 सुधारात्मक अधिकारी होने चाहिए। लेकिन केवल 1391 पद स्वीकृत किए हैं और काम केवल 886 कर रहे हैं। देश की जेलों में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। महिला आरक्षकों की भारी कमी है हर 30 कैदियों के लिए कम से कम एक सरकारी वकील होना अनिवार्य है। जो उनके मामलों की पैरवी कर सके, यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। छोटे-मोटे अपराधों में हजारों कैदी वर्षों से जेलों में बंद हैं। इनके मुकदमे का फैसला भी नहीं हो पा रहा है। सजा से अधिक बंद जेलों में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। जेलों में कैदियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन जेलों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। 2020 में देश में कुल जेलों की संख्या 1306 थी। जो वर्ष 2021 में बढ़कर मात्र 1319 हुई है। जबकि जेलों में कैदी बढ़ते ही

जा रहे हैं। सविधान के मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। 80 फीसदी परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। छोटे-मोटे अपराधों में जेल में बंद इन विचाराधीन कैदियों के बारे में न्यायालय को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कैदियों को एक निश्चित समय की सीमा के बाद व्यक्तिगत बांड लेकर जेल से रिहा करने अथवा जुर्माने की राशि माफ करने पर न्यायालयों और सरकारों को विचार करना चाहिए। विचाराधीन कैदियों में अधिकांश ऐसे कैदी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है, कि उनका परिवार दो वक्त की रोटी का आसानी से इंतजाम कर सके। ऐसी स्थिति में उनके लिए मुकदमा लड़ना या जमानत देना या जुर्माने की राशि भरना संभव ही नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को भी सोचना होगा कि विचाराधीन कैदी के रूप में छोटे-मोटे अपराधों में लिस बंद कैदियों को लंबे समय तक जेलों में बंद रखना इनके

मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए एक व्यापक सोच और नीति बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और न्यायपालिका इस समस्या पर सकारात्मक रुख अपनाए। इतनी बड़ी संख्या में जेलों में जो विचाराधीन कैदी बंद हैं। सामाजिक व्यवस्था और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्रहित में करने से ही राष्ट्र का फायदा होगा। जेलों में बंद रखकर हम उनकी स्वतंत्रता को तो बाधित कर ही रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी आबादी को निष्क्रिय बनाकर, सरकार के ऊपर खर्च बढ़ाकर हम कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास को बाधित कर रहे हैं। अब तो यह भी सुनने में मिल रहा है, कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण गरीब छोटे-मोटे अपराध कर जेल जाना जाता है। वहां दो वक्त का खाना मिल जाता है। जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में बने रहने के लिये जमानत नहीं कराते हैं। यदि यह सही है तो हम किस तरह का आर्थिक विकास कर रहे हैं। इसका चिंतन भी किया जाना चाहिए।

आर्थिक विषमता को गहरा करेगी नयी प्रौद्योगिकी

सुरेश शेट



आधुनिक जीवन में जब विकास यांत्रिक खोजों के सहारे होने लगा है तो व्यक्ति सोचने के लिए विवश हो गया है कि यह कृत्रिम विकास और उससे पैदा होने वाली यांत्रिक तीव्रता एक अभिशाप है या वरदान। जाहिरा तौर पर यह वरदान ही लगती है। रोबोट बनाए तो उन्होंने आदमी का रुचिकर या अरुचिकर काम करना शुरू कर दिया लेकिन उनके कारण जो लोग बेरोजगार हो गये उनके लिए यह तो अभिशाप ही है। उसी तरह से इंटरनेट, चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का विकास हुआ। विद्वानों ने कहा कि देख लो यह है वैश्विक अवधारणा के साथ असल वसुधैव कुटुम्बकम्। अच्छी बातें भी हैं इसमें, मरीज को चिकित्सा, दिल्ली में बेटे-बेटे विदेशों के महीना विशेषज्ञों द्वारा मिल सकती है और इसी प्रकार छात्र को शिक्षा भी जीवैट देने को तैयार बैठी है। हम 4जी से 5जी और 5जी से 6जी होते जा रहे हैं लेकिन यह त्वरित सूचना क्रांति ठगी का एक महान संकट भी पैदा करके आई है। वह संकट यह है कि कहीं आपने अपना ओटीपी नंबर बता दिया तो आपके बैंक खाते से राशि साफ हो जाएगी। त्वरित इंटरनेट शक्ति की कृपा से यह ठगी इतने संगठित रूप से होने लगी है कि दक्षिण भारत में बैठा हुआ टग उत्तर भारत के बैंकों से उनका धन खिसका सकता है। अभी यह सोच चल ही रही है कि यह यांत्रिक विकास मानवीय जीवन के लिए कितना सुविधाजनक है? सुविधाजनक तो ससमूह है अगर यह मानवीय व्यवहार का सहयोगी है। लेकिन यदि यह मानवीय व्यवहार पर छा जाने लगा और आदमी हर बात में गूगल पर निर्भर करने लगा तो उसमें से पूर्वाग्रहयुक्त जानकारी उसे गलत सोच के रास्ते पर भटक भी सकती है। लेकिन अभी एक नये आविष्कार ने दुनिया को हिला दिया। यह आविष्कार है चैटजीपीटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के धरातल पर यह एक चमत्कार करने वाला आविष्कार है जो आदमी के निर्देश पर एक क्षण में वह साब बता देता है जिसे लिखने, खोजने या सोचने में कई घंटे लग जाते हैं। उलझनों और सवालों के जवाब यहां हैं। बेशक लगता कि यह तो मौलिक चिंतन पर बहुत बड़ा आघात है लेकिन छात्रों से लेकर कर्मचारियों तक और कर्मचारियों से लेकर निर्देशकों तक -सब ने अपने निधम और प्रोजेक्ट आदि इस कृत्रिम बुद्धि के वरदान से तैयार करने शुरू कर दिए हैं लेकिन असल दुनिया पर नजर डालें तो दुनिया में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। खर्च करने की सामर्थ्य चंद लोगों की ही बढ़ी है, वहीं बहुतों की घट गई है। महंगाई ने उन्हें पंगु बना दिया है। ऐसी हालत में अगर चैटजीपीटी को बड़े पैमाने पर विद्यालयों से लेकर योजनाओं तक अपना लिया जाता है तो इसकी भारी-भरकम कीमत क्या निर्धन दंड सकेगा? फिलहाल इस चैटजीपीटी-4 को विकसित करने वाली कंपनी इसके लिए 20 डॉलर प्रति महीना मांग रही है यानी 3200 रुपये हर महीना। क्या देश के सब छात्र इसे दे सकेंगे? हालांकि यह सही है कि ये आविष्कार पहले की तुलना में बहुत उन्नत हैं। आर्थिक रूप से सक्षम कोई

शिक्षक, छात्र या मोटिवेशनल स्पीकर तो इसका इस्तेमाल करके अपने काम को चार चांद लगा लेगा। लेकिन छात्रों, शिक्षकों या व्यवसायियों का जो वर्ग इतनी कीमत नहीं चुका सकता, वे पिछड़ जाएंगे। हम लघु और कुटीर उद्योगों के विकास की बहुत बात करते हैं। इनकी रोजगार पैदा करने की सामर्थ्य की चर्चा भी बहुत है लेकिन अगर इसमें चैटजीपीटी को अपना लिया जाए तो इसकी लागत कहां जाएगी? बड़े उद्योगों के मुकाबले में छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए यह एक घाटे का सीधा ही होगी। मसलन बच्चों को ले लें। बहुत से बच्चे तो आरक्षण की छात्रवृत्ति से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास भोजन तक के पैसे नहीं, और वे मध्याह्न भोजन से गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों में क्या चैटजीपीटी बांटा जाएगा? तो वे शिक्षा संबंधी प्रतियोगिता में धनी स्कूलों का मुकाबला कैसे करेंगे? फिर चैटजीपीटी-4 की यह यांत्रिक शक्ति भाषाओं के लिए, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओं के लिए तो उनकी नाराजगी का कारण ही न बन जाए। अभी तक जो विकास चैटजीपीटी या चैटजीपीटी-4 का हुआ है, उसमें सही जानकारी अधिकतर अंग्रेजी भाषा में आ रही है। फिर इसके स्थानीयकरण की कोशिश होगी। इंटरनेट में अनुवाद करने वाली मशीनरी तो इतनी कमजोर है कि अर्थ का अर्थ कर देती है। जब तक यह तकनीक स्थानीय भाषाओं में विकसित होगी, तब तक तो न जाने दरिया में कितना पानी बह जाए। इसलिए अब जब शिक्षा, शोध और नौकरी तक नौजवान पीढ़ी को अपने प्रोजेक्ट तैयार करने पड़ेंगे तो क्या वे अंग्रेजी भाषा की ओर नहीं भागेंगे? जिस भाषा में यह चैटजीपीटी उन्हें सुविधा दे रहा है। वहीं चैटजीपीटी ने सुरक्षा की जानकारी में भेद लगाने भी शुरू कर दिए हैं। बहुत से देश तो इस आशंका से त्रस्त हो गए हैं कि इतनी असीम ताकत वाली बुद्धि का मशीनीकरण वह सह नहीं पाएंगे। चीन ने इस पर

प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसे डर है कि उसके अमेरिका जैसे शत्रु देश, इस यंत्र से उन्हें गलत जानकारियां देकर भटक सकते हैं। उस ने भी यही प्रतिबंध लगाया है। ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा और सीरिया में भी सुरक्षा कारणों से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन यांत्रिक विकास से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। जिन्होंने इसका विकास किया है, उन्हें इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के अवरोध भी बना देने चाहिए थे। दूसरी बात यह कि आखिर इस तकनीक का इस्तेमाल तो व्यक्ति को ही करना है। व्यक्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए ऐसी तरकीब पर प्रतिबंध की जरूरत नहीं बल्कि लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अगर हम मोबाइल और इंटरनेट क्रांति का पूरा प्रशिक्षण लोगों को प्रदान कर दें तो ठगी बंद हो जाएगी। चैटजीपीटी के इस्तेमाल का पूरा प्रशिक्षण साधारण आदमी को भी मिल जाए तो वह इसके गलत इस्तेमाल के रास्ते में दीवार बन जाएगा क्योंकि वह सही और गलत जानकारी की पहचान कर लेगा जैसा कि अभी गूगल के मामले में भी हो रहा है। लेकिन एक त्रुटि का निराकरण शायद न हो सके, वह है आर्थिक सामर्थ्य में असमानता का। वर्तमान में हर देश में गरीब और अमीर के बीच फासला बढ़ रहा है। करोड़पतियों के मुकाबले में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब या तो इस असमानता और भेदभाव को खत्म किया जाए या फिर तब तक ऐसी सामर्थ्यवान यांत्रिकता चंद धनकुबेरों की गटर में ही न डाल दी जाए। यांत्रिकता की सार्वभौमिकता व व्यापकता के लिए गरीबों के पक्ष में इसका निःशुल्क वितरण करना भी जरूरी होगा यदि असल में हम चाहते हैं कि गरीब और अमीर बौद्धिक रूप से एक जैसा विकास करें।

लेखक साहित्यकार हैं।

मध्यप्रदेश में ऊर्जा के नये स्रोतों का संरक्षण

(लेखक-नितय श्रीवास्तव)

मध्यप्रदेश में आपका स्वागत है। कभी आप इसे बीमार राज्य के रूप में जानते रहे होंगे लेकिन आज यह प्रदेश विकास का रोल मॉडल बना हुआ है। बुनियादी सुविधाओं से लबरेज मध्यप्रदेश की विकास की यह कहानी डेढ़ दशक पहले आरम्भ हुयी थी और आज प्रदेश का चम्पा -चम्पा विकास की गाथा सुन रहा है। सड़क, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य के साथ ही घटाघोष अंधेरे में रहने वाले मध्यप्रदेश के सैकड़ों गांव अब रोशन हो चुके हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये बिजली की रोशनी मिल रही है तो किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने के लिये बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली की कमी को पूरा करते हुए जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है उससे यह कहने में संकोच नहीं है, सन् 2024 के आते-आते आवश्यकता के अनुरूप बिजली पैदा होने लगेगी और मध्यप्रदेश स्थायी रूप से बिजली संकट से मुक्त हो जाएगा। यह कार्यालय शिवराज सिंह सरकार के सुनियोजित प्रयासों के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। बिजली उत्पादन और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश में काम जिस तेज गति से चल रहा है उससे संकेत मिलते हैं कि अब प्रदेशवासियों को बिजली संकट से पूर्णरूपेण निजा मिल जायेगी। उक्त दिशा में सरकार तो अपना प्रयास कर रही है,यदि जनभागीदारी भी सुनिश्चित हो तो लक्ष्य आसान हो जायेगा। सबका साथ,सबका विकास के सूत्र वाक्य को चरितार्थ करते हुए शिवराज सिंह सरकार ने गांव और गरीबों का ख्याल रखा है ताकि उनके हक की रोशनी कोई छीन न सके। मध्यप्रदेश में वर्तमान में नवकरणीय और पुनरोपयोगी ऊर्जा के बड़े कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 11 गुना नवकरणीय ऊर्जा का विस्तार हुआ है। प्रदेश में लगभग 5400 मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। प्रमुख नगरों और कस्बों में सौर ऊर्जा के महत्व पर ध्यान दिया जा रहा है। आमजन को ऊर्जा के व्यय तथा आयव्यय के प्रति जागरूक करने के अलावा ऊर्जा के पारम्परिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी

है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाने वाला ऊर्जा साक्षरता अभियान इस दिशा में अति महत्वपूर्ण साबित हो सका है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा। योजना में अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिये पहला तथ्य यह है कि सभी के व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण निहित हो। इसे एक अभियान के तहत हर गांव-शहर में गंभीरतापूर्वक लिया जाये तो हर व्यक्ति सतर्कता से ऊर्जा की बचत कर सकता है। कम लोग जानते होंगे कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध कुल बिजली आपूर्ति का 21 प्रतिशत हिस्सा नवकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। यहाँ यह भी बताते चलें कि विगत वर्ष दिसम्बर माह तक लगभग 5100 मेगावाट क्षमता की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गयी है। इसमें सौर ऊर्जा क्षमता 2432 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा क्षमता 2444 मेगावाट है। सौर ऊर्जा का और अधिक उत्पादन करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में मध्यप्रदेश दिनांदिन आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु असंतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाने के लिये मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने कई नवाचार किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सरकार द्वारा नवकरणीय ऊर्जा पॉलिसी 2022 बनाई गई है। प्रदेश में इसके पहले ऊर्जा स्रोत पर आधारित चार पृथक नीतियां लागू थीं। इनमें सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2012, पवन ऊर्जा नीति वर्ष 2012, लघु हाइड्रो ऊर्जा नीति वर्ष 2011 और बायोमास ऊर्जा नीति वर्ष 2011 है। अब राज्य सरकार द्वारा लागू नवकरणीय ऊर्जा नीति में आधुनिक ऊर्जा तकनीकों (हाइड्रिड, स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन आदि) तथा नवकरणीय ऊर्जा विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए कई प्रावधान किये गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों में "मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 22 हजार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। कोयला तथा पानी पर निर्भरता कम करते हुए सूरज और हवा से भी बिजली उत्पादन का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। मई 2023 तक आगर,नीमच एवं शाजापुर संयंत्रों में 1500 मेगावाट सौर बिजली पैदा होने

लगेगी। हमारे प्रयास के अनुरूप ऑकरेशर बांध में तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ग्रीन एनर्जी के संकल्प और स्वपन को पूरा करने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।" प्रकृति ने हमारे प्रदेश को ऐसी विशिष्ट स्थिति दी है कि यहाँ ज्यादातर हिस्सों में वर्ष भर में 200 से 250 दिनों तक खुलकर धूप निकलती है। यदि आकाश साफ हो तो किसी जगह की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा चार से लेकर सात किलोवाट प्रतिवर्ग किलोमीटर के मध्य होती है। वहीं ठंडे प्रदेशों के ध्रुवीय इलाकों को यह अनमोल वरदान नहीं मिला। सौर ऊर्जा के अनेक वैकल्पिक स्रोत हैं। यदि इन स्रोतों को पूरी तरह क्रियान्वित किया गया तो प्रदेश में होने वाली बिजली की खपत का पचास प्रतिशत हिस्सा इन सौर ऊर्जा के स्रोतों द्वारा पूरा किया जा सकता है। ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा मिला तो लक्ष्य के अनुरूप बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा के चलन को प्रवर्धित करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। फिर वर्तमान में ऐसे उपाय खोज लिये गए हैं जिनके द्वारा हम सौर ऊर्जा से सीधे अपनी ऊर्जा सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ बताते चलें कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की हर संभावना को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तलाशा जा रहा है। निश्चित रूप से सौर ऊर्जा एक उभरता हुआ क्षेत्र है अतः इसमें नित्य नये प्रयोग होते रहना चाहिये। सरकार सोलर पैनल या प्लेट निर्माण, बैटरी बनाने की दिशा में भी काम कर सकती है। इससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने से औद्योगिक विकास के नये रास्ते खुलेंगे। ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ ऊर्जा की बचत के बारे में भी गहन चिंतन होना चाहिये। यह एक ऐसा गंभीर विषय बन गया है जो सामान्य व्यक्ति के भी जीवन से गहरा सरोकार रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन में इसे जोड़ने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इस दिशा में सरकार के साथ जनभागीदारी जरूरी है।

क्षमता से अधिक विचाराधीन कैदी, स्वतंत्रता का अधिकार बाधित

(लेखक-सनत जैन)

भारत की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार जेल में 77 फीसदी विचाराधीन कैदी बंद है। इनमें से 68 फीसदी विचाराधीन कैदी अनपढ़ और आठवीं मिडिल स्कूल से कम पास हैं। यह कैदी दलित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं। इन कैदियों में 20 फीसदी कैदी मुसलमान हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षमता से अधिक कैदियों के जेल में होने के कारण, इनके मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वहीं इनके संवैधानिक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का भी हनन हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हर चार में से तीन कैदी विचाराधीन हैं। इनके पास जमानत के लिए नाहि संपत्ति होती है, और ना ही पैसे होते हैं। जिसके कारण यह छोटे-मोटे अपराधों में एक बार

जेल जाते हैं। जमानत के अभाव में वर्षों इन्हें जेल में बंद रखा जाता है। इनकी आर्थिक दृष्टि ऐसी नहीं होती है, कि यह अपना मुकदमा भी लड़ सकें। परिवारजन उन्हें आर्थिक संकट के चलते भी बंधोसे छोड़ देते हैं। 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था, कि 80 फीसदी कैदियों को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जेलों में बंद रखा गया। 2021 में रिहा किए गए 95 फीसदी विचाराधीन कैदियों को न्यायालय ने जमानत भी दी। लेकिन जमानत राशि नहीं भर पाने के कारण यह जेलों में बंद है। भारत के 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता से अधिक कैदी पिछले कई वर्षों से बंद है। इसमें सबसे ज्यादा बिहार की हालत खराब है। जहां 140 फीसदी से अधिक कैदी हैं। उत्तराखंड में 185 फीसदी क्षमता से अधिक कैदी बंद है। रिपोर्ट के अनुसार 391 जिलों में, क्षमता की तुलना में 150 फीसदी तथा 709 जिलों में 100 फीसदी से अधिक कैदी बंद हैं। आदर्श

कारावास नियमावली के अनुसार 200 कैदियों पर एक सुधारात्मक अधिकारी और 500 कैदियों पर एक मनोचिकित्सक होना अनिवार्य है। जेलों में 2770 सुधारात्मक अधिकारी होने चाहिए। लेकिन केवल 1391 पद स्वीकृत किए हैं और काम केवल 886 कर रहे हैं। देश की जेलों में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है। महिला आरक्षकों की भारी कमी है हर 30 कैदियों के लिए कम से कम एक सरकारी वकील होना अनिवार्य है। जो उनके मामलों की पैरवी कर सके, यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। छोटे-मोटे अपराधों में हजारों कैदी वर्षों से जेलों में बंद हैं। इनके मुकदमे का फैसला भी नहीं हो पा रहा है। सजा से अधिक बंद जेलों में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। जेलों में कैदियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन जेलों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। 2020 में देश में कुल जेलों की संख्या 1306 थी। जो वर्ष 2021 में बढ़कर मात्र 1319 हुई है। जबकि जेलों में कैदी बढ़ते ही

जा रहे हैं। सविधान के मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। 80 फीसदी परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। छोटे-मोटे अपराधों में जेल में बंद इन विचाराधीन कैदियों के बारे में न्यायालय को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कैदियों को एक निश्चित समय की सीमा के बाद व्यक्तिगत बांड लेकर जेल से रिहा करने अथवा जुर्माने की राशि माफ करने पर न्यायालयों और सरकारों को विचार करना चाहिए। विचाराधीन कैदियों में अधिकांश ऐसे कैदी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी नहीं है, कि उनका परिवार दो वक्त की रोटी का आसानी से इंतजाम कर सके। ऐसी स्थिति में उनके लिए मुकदमा लड़ना या जमानत देना या जुर्माने की राशि भरना संभव ही नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को भी सोचना होगा कि विचाराधीन कैदी के रूप में छोटे-मोटे अपराधों में लिस बंद कैदियों को लंबे समय तक जेलों में बंद रखना इनके

मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए एक व्यापक सोच और नीति बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और न्यायपालिका इस समस्या पर सकारात्मक रुख अपनाए। इतनी बड़ी संख्या में जेलों में जो विचाराधीन कैदी बंद हैं। सामाजिक व्यवस्था और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल राष्ट्रहित में करने से ही राष्ट्र का फायदा होगा। जेलों में बंद रखकर हम उनकी स्वतंत्रता को तो बाधित कर ही रहे हैं। वहीं इतनी बड़ी आबादी को निष्क्रिय बनाकर, सरकार के ऊपर खर्च बढ़ाकर हम कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास को बाधित कर रहे हैं। अब तो यह भी सुनने में मिल रहा है, कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण गरीब छोटे-मोटे अपराध कर जेल जाना जाता है। वहां दो वक्त का खाना मिल जाता है। जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में बने रहने के लिये जमानत नहीं कराते हैं। यदि यह सही है तो हम किस तरह का आर्थिक विकास कर रहे हैं। इसका चिंतन भी किया जाना चाहिए।



चीन की जीडीपी 2023 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत बढ़ी

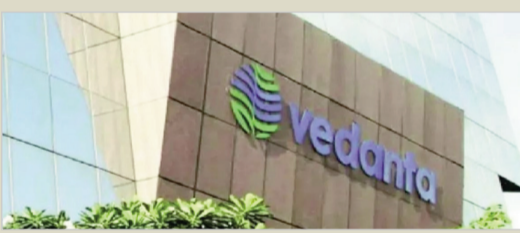
बीजिंग। चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2023 की पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इस दौरान खपत और खुदरा बिक्री बढ़ने से अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार द्वारा कोविड महामारी को लेकर सख्त नीति को छोड़ने के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। पिछले साल की इसी अवधि जनवरी-मार्च 2022 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत थी। कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद बाजारों और रेस्टोरेंट में लोगों की आवाजाही बढ़ी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद को समर्थन मिला। मार्च में उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत बढ़ी। साल के पहले दो महीनों में यह आंकड़ा 7.1 प्रतिशत था। मार्च 2023 में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 3.9 प्रतिशत बढ़ा।

मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलेगा

नई दिल्ली। दवा बनाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक निगम) 25 अप्रैल को खुलेगा। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आएफपी) के अनुसार तीन दिन का आईपीओ 27 अप्रैल को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 24 अप्रैल को खुलेगी। इस आईपीओ के तहत कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है, और यह पूरी तरह प्रवर्तकों और अन्य मौजूदा शेयरधारकों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है। ओएफएस में शेयर बेचने वालों में प्रवर्तक रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा और शीतल अरोड़ा शामिल हैं। इसके अलावा, केयनहिल सीआईपीईएफ, केयनहिल सीजीपीई, बेज लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी अपने शेयर बेच रहे हैं। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश के रूप में है, इसलिए इससे कंपनी को कोई राशि नहीं मिलेगी और निगम से जुटाई गई पूरी धनराशि शेयरधारकों के पास जाएगी।

वेदांता ने 20 कोरियाई कंपनियों के साथ डिस्प्ले केंद्र के लिए समझौता किया

मुंबई। वेदांता समूह ने कहा कि उसने भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के विकास के लिए डिस्प्ले ग्लास क्षेत्र से जुड़ी 20 कोरियाई कंपनियों के साथ समझौता किए हैं। हाल ही में संपन्न कोरिया बिज-ट्रेड शो 2023 में वेदांता समूह को एक रोडशो के लिए आमंत्रित किया गया था। इस शो का आयोजन कोरियाई सरकार के व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन निकाय कोटा ने किया था। वेदांता के सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले कारोबार के एक वे रिष्ठ ओ धिकारी ने कहा कि 20 कोरियाई कंपनियों के साथ समझौता जापानों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोरिया की 50 से अधिक कंपनियों ने वेदांता के साथ साझेदारी करने में रुचि दिखाई थी। इस बयान में उन्होंने भारत में एक डिस्प्ले विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की वेदांता की योजना की जानकारी देने के साथ संभावित साझेदारों एवं उपभोक्ताओं को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार की अनुकूल नीतियों से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स का गढ़ बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं। वेदांता का डिस्प्ले विनिर्माण केंद्र इस प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। वेदांता और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम ने गुजरात में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा वेदांता ने एक डिस्प्ले इकाई लगाने का भी आवेदन किया है। यह इकाई मोबाइल फोन, टेलीविजन एवं अन्य डिजिटल उत्पादों के लिए स्क्रीन बनाने का काम करेगी।



मुंबई में खुला एप्पल का पहला रिटेल स्टोर, देसी ढोल की थाप पर कुक ने किया ग्राहकों का स्वागत

स्टोर से बाहर निकलकर लोगों के साथ सेल्फी ली

मुंबई। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने देश में कंपनी का पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर खोलने पर देसी ढोल की थाप के बीच लोगों की भारी भीड़ और पहले ग्राहकों का अभिवादन किया। कुक मुंबई के रिटेल स्टोर से निकले और बड़ी संख्या में आए एप्पल खरीदारों के साथ सेल्फी ली। उन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) वित्तीय, कला और मनोरंजन जिले में स्थित एप्पल बीकेसी में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में ग्राहकों का स्वागत किया। मुंबई में नए एप्पल फ्लैगशिप रिटेल स्टोर, उसके बाद नई दिल्ली में एक और स्टोर आने वाले वर्ष में एप्पल के विकास को बढ़ावा देगा। रिटेल के एप्पल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिपेंद्र ओब्रायन ने कहा, एप्पल बीकेसी मुंबई की जीवंत संस्कृति का प्रतिबिंब



है और कनेक्शन और समुदाय के लिए एक सुंदर, स्वागत योग्य स्थान में एप्पल के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाता है। एप्पल बीकेसी मंगलवार से गर्मियों तक चलने वाली एप्पल सीरीज मुंबई राइजिंग में आज विशेष पेशकश करेगा। एप्पल बीकेसी को दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल एप्पल स्टोर स्थानों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। स्टोर परिचालन रूप से कार्बन न्यूट्रल है, जो 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पर चल रहा है। प्रत्येक टाइल को लकड़ी के 408 टुकड़ों से बनाया गया है, जिसमें प्रति टाइल 31 मांझ्यूल

नोएडा पावर को बिजली वितरण इकाइयों की सूची में 'ए' रेटिंग

नई दिल्ली।

बिजली मंत्रालय की वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी विद्युत वितरण कंपनियों की रैंकिंग में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने 'ए' रेटिंग हासिल की है। आरपीसीएल ग्रेटर नोएडा समूह और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक

विकास प्राधिकरण की संयुक्त उद्यम कंपनी एनपीसीएल ने एक बयान में कहा कि यह रेटिंग विभिन्न मानकों मसलन परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन, नियामक अनुपालन, ग्राहक सेवा और ऊर्जा दक्षता पर आधारित है। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक

अधिकारी (सीईओ) पीआर कुमार ने कहा कि बिजली मंत्रालय से मिला यह सम्मान हमें और बेहतर प्रदर्शन करने तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट कराए जाने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एनपीसीएल ग्रेटर नोएडा बिजली वितरण करती है। बिजली

मंत्रालय की 2021-22 की वितरण कंपनियों की उपभोक्ता सेवा रेटिंग शीर्षक से हल में जारी रिपोर्ट में 70 वितरण कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें 12 वितरण कंपनियां शामिल नहीं हुईं। यानी कुल 58 वितरण कंपनियों में से नौ को 'ए' रेटिंग दी गई है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुंबई।

मुंबई शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी गिरावट पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी होने से बाजार में गिरावट आई जो अंत तक बनी रही। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों वाला बीएसई सूचकांक संसेक्स 183.74 अंक करीब 0.31 फीसदी नीचे आकर 59,727.01 अंक पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान संसेक्स 60,113.47 के उच्च स्तर पर जाने के बाद 59,579.30 तक गिरा। इसी प्रकार नेशनल

स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी 46.70 अंक तकरीबन 0.26 फीसदी फिसलकर 17,660.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 17,766.60 की उंचाई तक ऊपर जाने के बाद 17,610.20 तक गिरा। कारोबार के दौरान संसेक्स के शेयरों में से 14 शेयर लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया, विप्रो, और मासुति संसेक्स के शीर्ष पांच शेयरों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर सबसे ज्यादा 2.17 फीसदी तक उछले। वहीं दूसरी ओर संसेक्स के शेयरों में 16 शेयर नुकसान के साथ ही लाल निशान पर बंद हुए। पावर ग्रिड, अट्रॉपेटेक सीमेंट, टाइटन, रिलायंस और बजाज

फिनसर्व सबसे अधिक नुकसान वाले शीर्ष पांच शेयर रहे। इसमें भी पावर ग्रिड के शेयरों सबसे अधिक 2.45 फीसदी तक गिरा। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बीच ही बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई है। संसेक्स 99.64 अंक की बढ़त के साथ 60,010.39 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 26.20 अंक की बढ़त के साथ 17,733 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। प्री-ओपनिंग में बाजार की मिलीजुली शुरुआत हुई है। संसेक्स 83.48 अंक की गिरावट के साथ 59,827.27 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि निफ्टी 79.70 अंक की बढ़त के साथ 17,786.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

टीसीएस के कर्मचारियों को मिलेगा 12 से 15 फीसदी इंक्रीमेंट!

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस अपने टॉप परफॉर्मिंग कर्मचारियों को 12 से 15 फीसदी तक इंक्रीमेंट दे सकती है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को उम्मीद है कि इस कदम से नौकरी छोड़ने या बदलने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी। अभी कंपनी में एप्रिल रेट 20 फीसदी है जो इस वित्त वर्ष के दूसरे हाफ में घटकर 13 से 14 फीसदी रह सकता है। साथ ही कंपनी कैम्पस रिक्तियों के लिए भी बेस सैलरी में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अगर टीसीएस ऐसा करती है तो आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनियों को भी इस तरह का फैसला लेना पड़ सकता है। आईटी सेक्टर में नौकरियों की संख्या कम हो रही है लेकिन टीसीएस ने पिछले वित्त वर्ष में कैम्पस से 44,000 भर्तियां कीं। इस साल कंपनी की योजना कैम्पस से 40,000 लोगों को भर्ती करने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस के चीफ ह्यूमन रिसोर्सिंग ऑफिसर मिलिंद लच्छू ने कहा कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 12 से 15 फीसदी सैलरी हाइक देने पर विचार कर रही है। बाकी कर्मचारियों को 1.5 फीसदी से आठ फीसदी तक का इंक्रीमेंट मिल सकता है। पिछले साल कंपनी ने जूनियर लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 11 फीसदी बोनस दिया था जबकि सीनियर लेवल पर कम बोनस दिया गया था। इसके अलावा जनवरी-मार्च की पहली तिमाही में जूनियर एग्जीक्यूटिव्स को 100 फीसदी बोनस दिया गया। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 821 नए कर्मचारियों को भर्ती की जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यह संख्या 35,209 थी।

टेस्ला को नया इंटीरियर पर्सनलाइजेशन सिस्टम पेटेंट मिला

सैन फ्रांसिस्को।

एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला को एक नए इंटीरियर पर्सनलाइजेशन सिस्टम के लिए पेटेंट मिला है, जो संभावित रूप से अपने वाहनों को पहुंच और आराम को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पेटेंट कार्यालय में हाल ही में दायर पेटेंट आवेदन से पता चलता है कि कंपनी एक उन्नत निजीकरण प्रणाली विकसित कर रही है जो ऑटोमेटिक उद्योग में मौजूदा तकनीकों को पार कर सकती है। नया पर्सनलाइजेशन सिस्टम कार के इंटीरियर कैमरा सिस्टम का उपयोग करने वालों को पहचान करेगा, उनके आकार का अनुमान लगाने और आराम और उपयोग में आसानी के लिए सेटिंग्स को वैयक्तिकृत करने के

लिए करेगा। रिपोर्ट के अनुसार यह सामने की सीट पर रहने वालों की ऊंचाई के आधार पर फुट सीट और कंट्रोल पोजिशनिंग सहित कई सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता है, पूरे केबिन में कहां और कितने लोग बैठे हैं जो ऑडियो सेटिंग्स के आधार पर एयर कंडीशनिंग वेंट्स की दिशा और उपयोग सुनिश्चित करते हैं। केवल रहने वालों को अधिक आरामदायक बनाने के अलावा, बेहतर निजीकरण प्रणाली से टेस्ला की मौजूदा सुरक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। वाहन अक्षम व्यक्तियों का पता लगा सकता है और या तो आपातकालीन सेवाओं को बुला सकता है या शायद व्यक्ति को



अस्पताल ले जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा इन उपकरणों को कार की टक्कर के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जा सकता है कि वाहन यात्रियों को चोट न लगे। इस बीच वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को मात देते हुए टेस्ला ने 2023 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 4,22,875 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की है। पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने 4,40,000 से अधिक वाहनों का उत्पादन किया।

सैमसंग ने भारत में गैलेक्सी एम14 5जी लांच किया

मुंबई।

सैमसंग ने 50 एमपी ट्रिपल कैमरा, 6000 एमएच बैटरी, 5 एनएम प्रोसेसर और डेर सारे फीचर्स के साथ गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन लांच करने की घोषणा की। फुल एचडी प्लस 90हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ 6.6-इंच एम14 5जी की कीमत 13,490 रुपये (4 प्लस 128 जीबी) और 6 प्लस 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 14,990 रुपये है। गैलेक्सी एम14 5जी की बिक्री 21 अप्रैल को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। सैमसंग इंडिया के मोबाइल बिजनेस के निदेशक राहुल पाहवा ने कहा, 2019 में लांच होने के बाद से, गैलेक्सी एम सीरीज ने भारत में लाखों उपभोक्ताओं का धार

और प्रशंसा प्राप्त की है। एफ 1.8 लेंस लो-लाइट फोटोग्राफी को बहुत स्पष्टता के साथ सक्षम बनाता है। सैल्फ़ी के लिए डिवाइस में 13 एमपी का फ्रंट कैमरा है। अपनी 6000 एमएच बैटरी के साथ, गैलेक्सी एम14 5जी बिना चार्ज किए दो दिन तक चलने का दावा करता है। कंपनी ने कहा कि स्मार्टफोन 25वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो आपके फोन को खरिदते समय में रिचार्ज कर सकता है। डिवाइस में मल्टी-टारिकिंग के लिए सेगमेंट-अग्रणी 5एनएम एक्ससीनोस



यह एंड्रॉइड 13 पर आधारित वन यूआई 5.1 कोर के साथ आता है। सैमसंग ने कहा कि वह गैलेक्सी एम14 5जी के लिए ओएस अपग्रेड की 2 जेनरेशन और 4 साल तक का सिक्वियरिटी अपडेट सुझाया जाएगा।

1330 प्रोसेसर है। गैलेक्सी एम14 5जी रैम प्लस फीचर के साथ 12 जीबी तक रैम के साथ आता है। जब व्यक्तिगत डेटा और एप्लिकेशन को स्टोर करने की बात आती है, तब यह डिवाइस बड़ी हुई सुरक्षा और प्राइवैसी के लिए सिक्वोर फोल्डर का समर्थन करता है।

देश में 2022-23 में 15 फीसदी बढ़ा यात्री वाहनों का निर्यात

मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, 2.5 लाख से अधिक इकाइयों का निर्यात किया

नई दिल्ली।

देश से यात्री वाहनों का निर्यात वर्ष 2022-23 में 15 प्रतिशत बढ़कर 6,62,891 इकाई रहा। इसमें 2.5 लाख से अधिक इकाइयों का निर्यात करने वाली मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। उद्योग संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में कुल यात्री वाहनों का निर्यात 6,62,891 इकाई रहा है जो 2021-22 में 5,77,875 इकाई था। आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में यात्री कारों का निर्यात दस प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,13,787 इकाई रहा। वहीं उपयोगी (यूटिलिटी) वाहनों का निर्यात 23 प्रतिशत बढ़कर 2,47,493 इकाई रहा। हालांकि वैन का निर्यात घट गया और 2022-23 में यह 1,611 इकाई रहा जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 1,853 इकाई था। पिछले वित्त वर्ष में यात्री वाहन श्रेणी के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मारुति सुजुकी इंडिया की रही।

इसके बाद हुंदै मोटर इंडिया और किआ इंडिया का स्थान रहा। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी ने 2022-23 में 2,55,439 यात्री वाहनों का निर्यात किया जो 2020-21 में निर्यात किए गए 2,35,670 वाहनों से आठ प्रतिशत अधिक है। हुंदै मोटर इंडिया ने 1,53,019 वाहनों का निर्यात किया जो 2021-22 की 1,29,260 इकाइयों से 18 प्रतिशत अधिक है। किआ इंडिया ने 2022-23 में 85,756 वाहनों का निर्यात किया जबकि 2021-22 में उसने 50,864 इकाइयों का निर्यात किया था। निसान मोटर इंडिया ने 60,637 वाहनों का, रेनो इंडिया ने 34,956 वाहनों का; फॉक्सवैगन इंडिया ने 27,137 इकाइयों का निर्यात किया। होंडा कार्स ने 22,710 इकाइयों का जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2022-23 में 10,622 इकाइयों का निर्यात किया। बीते वित्त वर्ष में भारत से वाहनों का कुल निर्यात 47,61,487 इकाई रहा है जो 2021-22 की 56,17,359 इकाइयों से 15 प्रतिशत कम है।

एवलॉन के शेयर पहले दिन एक प्रतिशत गिरकर सूचीबद्ध हुए

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संबंधी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर पहले दिन एक प्रतिशत गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर बीएसई पर निगम मूल्य के मुकाबले 1.14 प्रतिशत गिरकर 431 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। बाद में शेयर 5.43 प्रतिशत टूटकर 421.30 रुपए के भाव पर आ गए। एनएसई पर एवलॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर निगम मूल्य 436 रुपए पर सूचीबद्ध हुए, हालांकि बाद में इसमें 2.98 प्रतिशत की गिरावट हुई। कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) को 2.21 गुना अभिमान मिला था। कंपनी के 865 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 415-436 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था।



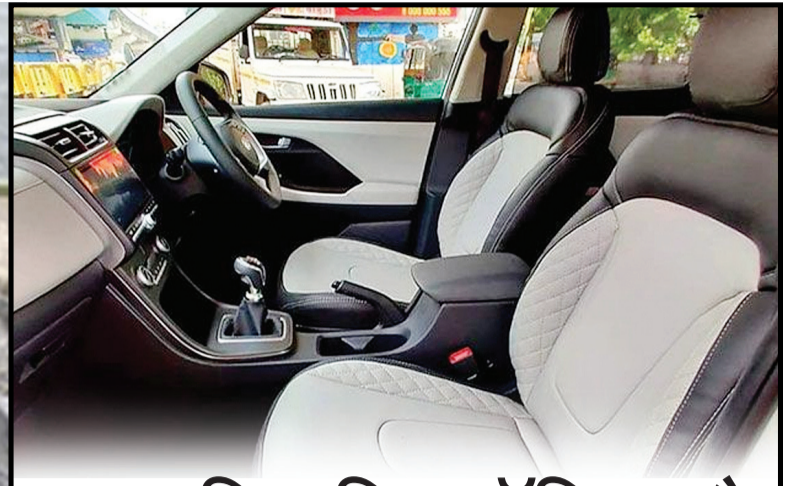
खाने के तेल की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा

नई दिल्ली।

विदेशी बाजारों में सुधार के रुख के बीच स्थानीय दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेल-तिलहन कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। मांग कमजोर होने से जहां सरसों तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन कीमतों में गिरावट आई वहीं मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज के मजबूत होने से सोयाबीन डीगम, कच्चा पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन के साथ साथ बिनौला तेल कीमतों में मामूली सुधार देखने को मिला जबकि मूंफली तेल तिलहन, सोयाबीन दिल्ली और सोयाबीन इंदौर तेल के भाव पूर्वस्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 2-2.5 प्रतिशत की तेजी है जबकि शिकागो एक्सचेंज में एक प्रतिशत की तेजी है। सोमवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे- सरसों तिलहन 5,095-5,190 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपए प्रति क्विंटल। मूंफली 6,790-6,850 रुपए प्रति क्विंटल। मूंफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) 16,660 रुपए प्रति क्विंटल। मूंफली रिफाईंड तेल 2,535-2,800 रुपए प्रति टिन।



सरसों तेल वादरी 9,950 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी 1,590-1,660 रुपए प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 1,590-1,710 रुपए प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी 18,900-21,000 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली 10,780 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला 8,600 रुपए प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा) 9,400 रुपए प्रति क्विंटल। पामोलीन आरबीडी, दिल्ली 10,100 रुपए प्रति क्विंटल। पामोलीन एक्स कांडला 9,250 रुपए (बिना जीएएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना 5,355-5,405 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन लूज 5,105-5,205 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का खल (सरिस्का) 4,010 रुपए प्रति क्विंटल।



बहुत क्रिएटिव कॅरियर है कार एसेसरीज डिजाइनिंग

एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं।

कार एसेसरीज डिजाइनिंग एक ऐसा कॅरियर क्षेत्र है, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी होती है। लेकिन यह एक ऐसा क्रिएटिव कॅरियर क्षेत्र है, जिसमें ग्रोथ की संभावना बहुत अधिक है। यह एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर के काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह केवल कारों और इसके सामान के लिए पूरा करता है। कार एसेसरीज डिजाइनर ऐसे व्यक्ति हैं जो कार एसेसरीज और पाटर्स के लिए नए डिजाइन बनाते हैं। वे न केवल देखभाल की संरचना में सुधार करते हैं, बल्कि इसकी कार्यक्षमता भी बढ़ाते हैं। ऐसा करते समय, एक कार एसेसरीज डिजाइनर को वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और दिए गए मापदंडों के तहत काम करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस कॅरियर क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक बता रहे हैं -

क्या होता है काम
एक कार एसेसरीज डिजाइनर तीन क्षेत्रों में से एक में काम करते हैं - इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग या कलर और ट्रिम डिजाइन। वे ड्राइंग, मॉडल और प्रोटोटाइप का उपयोग करके कार एसेसरीज पाटर्स, असेंबली और सिस्टम के ड्राफ्टिंग डिजाइन बनाते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि वे कार को विजुअली अधिक अपीलिंग बनाएं।

स्किल्स - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि एक कार एसेसरीज डिजाइनर को हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जो वाहन में उपयोग होने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें ग्राहक की पूरी आवश्यकता को समझना चाहिए और डिजाइन और इसके उत्पादन के उपयोग के बारे में बड़े पैमाने पर शोध करना चाहिए। उनके भीतर कुछ अलग व हटकर सोचने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर व कार का तकनीकी ज्ञान उनके काम को अधिक आसान बनाता है।

योग्यता - एक कार एसेसरीज डिजाइनर बनने के लिए डिजाइन के प्रासंगिक विशेषज्ञता में कम से कम स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन, बीएससी इन डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बी डीएस इन ऑटोमोटिव डिजाइन करके इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। जिस विश्वविद्यालय या कॉलेज से उम्मीदवार अपनी डिग्री हासिल करता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

आमदनी - कॅरियर एक्सपर्ट बताते हैं कि इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व क्रिएटिविटी के आधार पर बढ़ती जाती है। हालांकि एक कार एसेसरीज डिजाइनर की एवरेंज सालाना सैलरी सात से आठ लाख के बीच होती है।

प्रमुख संस्थान
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नवी मुंबई
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद
एरिना एनिमेशन, बैंगलोर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बैंगलोर
फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई
वीआईडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली
वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मैनेजमेंट, नई दिल्ली



2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें।

आसान और लाभकारी बिजनेस है मत्स्य पालन कॅरियर के हैं भरपूर अवसर

भारत भर में मत्स्य पालन एक जाना पहचाना व्यवसाय रहा है। कृषि से इसको जोड़कर जरूर देखा जाता रहा है, किंतु हकीकत में यह काफी उन्नत और लाभकारी व्यवसाय है। वर्तमान में कोरोनावायरस के कारण बड़ी संख्या में गांवों की ओर लोगों का पलायन हुआ है। कई लोगों को रोजगार की समस्या भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि जमे जमाए व्यवसाय या फिर शहर में करने वाली नौकरी छूटने के बाद लोग गांव की ओर लौटे हैं। गांव में चूँकि अधिकतर लोगों के पास कम-अधिक जमीन होती ही है और ऐसी स्थिति में मत्स्य पालन उन सबके लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है।

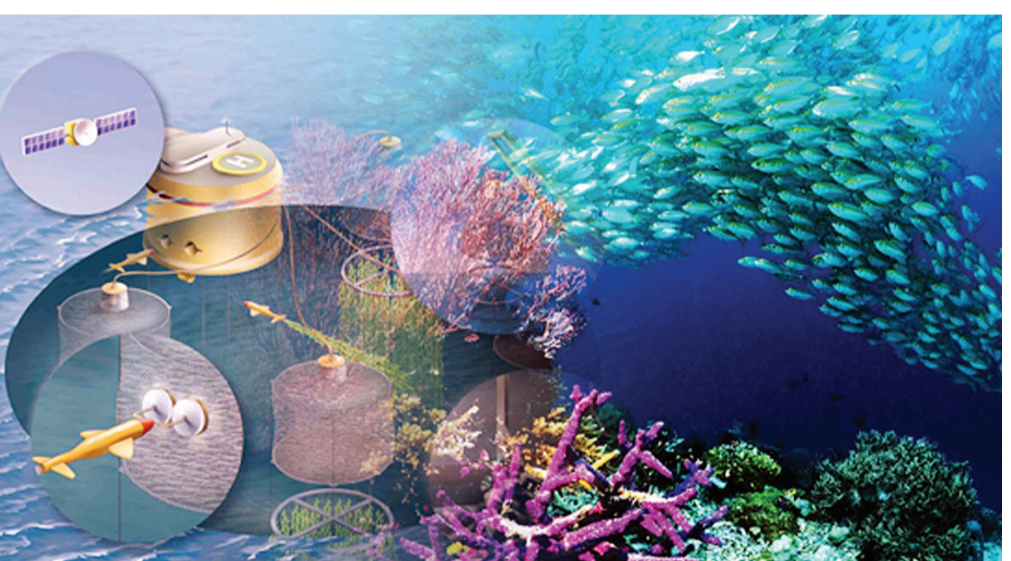
तालाब को ठीक से करें तैयार
अक्सर लोग किसी तालाब की खुदाई के बाद तुरंत ही मछली के बीज डाल देते हैं, लेकिन यह ठीक मेथड नहीं है। सबसे पहले तालाब की सफाई करने के बाद उसमें 200 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूने का छिड़काव जरूरी है। इसके अलावा महुए की खली और ब्लीचिंग पाउडर डालने से भी मछली पालन के लिए तालाब बेहतर कंडीशन में तैयार हो जाता है। यह सारा कार्य आप टंड के मौसम में ही कर लें, ताकि टंड का मौसम बीतते-बीतते मछली का बच्चा डालने योग्य आप का तालाब तैयार हो जाए। साथ ही तालाब में ढ़ांचा नामक घास भी बोया जाता है, ताकि बाद में वह खाद बन जाए और मछली पालन के लिए उपयुक्त रहे। यह तकरीबन 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब में बोया जाता है। साथ ही गोबर की खाद डालने से भी वनस्पति जल्दी उग जाती है। अगर समय पर तालाब में अच्छी घास नहीं होती है तो गोबर के साथ सुपर फास्फेट और यूरिया का घोल तालाब में डालना लाभकारी हो सकता है। हालांकि मछली का बीज डालने से काफी पहले ही यह कार्य करना चाहिए। मछली का बीज डालने के बाद खाद डालना खतरनाक हो सकता है। उपरोक्त कार्य करने के कम से कम 1 महीने बाद ही तालाब में पानी भरकर, टंड का मौसम बीतने के बाद मछली का बीज डालें। साथ ही तालाब के पानी की गुणवत्ता और उस में ऑक्सीजन की ठीक मात्रा हो, इसके प्रति अतिरिक्त सजगता आवश्यक है।

मछलियों की ब्रीड पर खास ध्यान दें
अगर आपका तालाब ठीक ढंग से तैयार हो गया है, किंतु मछलियों के बीज आप सही ढंग से नहीं डालते हैं, तो आपके लिए यह लाभकारी नहीं रहेगा। मुख्य रूप से देशी और विदेशी ब्रीड की मछलियां लोग डालते हैं। इसमें देशी में रोहू, कतला, मुगल इत्यादि प्रचलित प्रजातियां हैं, तो विदेशियों में सिल्वर कर्प, ग्रास कार्प इत्यादि प्रमुख हैं। कई लोग जब बाहर से मछली लेकर आते हैं तो उसे एक दो परसेंट नमक के घोल में कुछ देरी के लिए रखते हैं, ताकि अगर मछली के बीज में कोई बीमारी है तो उसका असर कम हो जाए। हालांकि यह बहुत देर तक नहीं

होना चाहिए और 2 से 3 मिनट के बाद मछली के बच्चों को तालाब में डाल देना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मछलियों की मात्रा तालाब में ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप तालाब में सही अनुपात में मछलियों का बीज डालें। अगर एक या दो मछली आपके तालाब में मर जाती हैं, तो उसे तत्काल निकाल कर बाहर करें समय-समय पर बीज की वृद्धि और उसकी जांच करना आपको नुकसान से बचा सकता है। मछलियों के लिए यू तो किसी विशिष्ट चारे की जरूरत नहीं होती है, खासकर तब जब आप का तालाब पुराना हो गया हो, किंतु चावल का आटा और मूंगफली की खली इत्यादि मछलियों को तेजी से बढ़ाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त चारे की मात्रा मछलियों के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, इसके प्रति भी सजग रहें। ध्यान दें मछली का बीज सही क्वालिटी का हो, तो सही मात्रा में भी अवश्य हो, अन्यथा बाद में मछलियां ठीक ढंग से बढ़ेंगी नहीं।

मार्केट को समझना जरूरी है
अब जब आपके पास मछली के बीज तैयार हो जाते हैं तो आसपास की मार्केट का एक अध्ययन जरूर करें और देखें कि आपके आसपास किस तरह की मछलियों की खपत ज्यादा होती है। लोग आखिर क्यों खरीदते हैं? ऐसे में जब आप मछली मार्केट जाएंगे, तो एक ग्राहक बनकर मछलियों की ब्रीड से लेकर उसकी कीमत तक का पता कर

सकते हैं। उसी अनुरूप आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर बड़ी मछलियों की खपत अधिक है, तब आपके तालाब में कम मछलियों का बीज रहना चाहिए, जबकि अगर छोटी मछलियों की खपत है तो तालाब में बीज अगर अधिक भी डालेंगे तो आपको फायदा ही होगा। कुल मिलाकर सही टाइम पर मछलियों को बेचना और सही व्यापारियों से संपर्क में रहना आपको लाभ दिला सकता है। कई बार मछली के व्यापारी आपके तालाब पर आकर खुद ही सारी मछलियां ले जाते हैं। हालांकि रेट में अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप मछलियों को खुद भी मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है। मतलब अगर आपके तालाब में कुछ मछलियां बड़ी हो गई हैं और कुछ मछलियां छोटी हैं, तो बड़ी मछलियों को या तो निकाल कर दूसरे तालाब में डालें या उन्हें मार्केट में भेज दें, क्योंकि बड़ी मछलियों का आहार अधिक होगा और वह छोटी मछलियों का चारा भी खा जाएंगी। इसलिए मछलियों की ग्रेडिंग करना आवश्यक है ताकि मछलियों की ग्रोथ में एक निरंतरता रहे। साथ ही मछलियों में इंटरनल और एक्सटर्नल बीमारी के प्रति सजग रहें, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी पूँजी भारी नुकसान में बदल गयी। इसके अलावा नई नई जानकारियां आप भिन्न माध्यमों से लेते रहें और अलग-अलग मछली पालकों के संपर्क में रहें। ऐसे में नई चीजें आपको पता चलेंगी।



कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। ऑपरेशन्स मैनेजमेंट आपके भविष्य के कॅरियर के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों के निवेश की एक लंबी प्रक्रिया है। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया विभिन्न अवधारणाओं को अपनाती है, जैसे - आत्म-जागरूकता, कॅरियर विकास योजना और कॅरियर अन्वेषण, जीवन भर सीखने की क्षमता और नेटवर्किंग। कॅरियर में अर्थ-कुशल से लेकर कुशल और अर्थ पेशेवर से पेशेवर तक के सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं। कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ शुरू होती है। यह कार्य थोड़ा कठिन हो सकता है, जब व्यक्ति के पास कॅरियर के अवसरों और उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। हालांकि, पूरी कॅरियर प्रबंधन प्रक्रिया परिभाषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापना पर ही आधारित होती है।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य
सामान्य शब्दों में परिचालन प्रबंधन किसी संगठन के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से एक कुशल तरीके से सामग्रियों

और श्रम को वांछित वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करने से संबंधित है। यह उपलब्ध संसाधनों की खरीद और उपयोग करके उत्पादन को अधिकतम करता है, जिसमें कच्चे माल, उपकरण, प्रौद्योगिकी, सूचना और अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उत्पादन की प्रक्रिया की योजना, डिजाइनिंग, आयोजन, नियंत्रण और अनुकूलन के साथ इसका अधिक सम्बन्ध होता है। संचालन प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि एक इकाई कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक इनपुट को आउटपुट में कैसे बदल देती है। यह स्पष्ट है कि संचालन प्रबंधन डिलीवरी ऑरिएंटेड होता है। हालांकि, संचालन प्रबंधन को लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के समान नहीं माना जाना चाहिए। संचालन प्रबंधन व्यापक है और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन इसका एक हिस्सा है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन किसी अभियान, योजना, परियोजना या रणनीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों, सामग्री और अन्य संसाधनों की खरीद, निष्पादन और नियंत्रण की योजना बनाता है। विनिर्माण और सेवा संगठनों दोनों को ही संचालन प्रबंधन के कार्य की आवश्यकता होती है, जो एक प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंत तक कवर करता है। सदियों से विनिर्माण उद्योग फल-फूल रहे हैं। अब सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ परिचालन प्रबंधकों के लिए अवसर कई गुना बढ़ गए हैं।

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में कॅरियर बनाने के लिए क्या करें ?

ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में कॅरियर बनाने के लिए क्या करें ?
अन्य विषयों की तरह प्रबंधन शिक्षा में भी कई विषय होते हैं। प्रबंधन के छात्रों को प्रबंधन के सभी प्रमुख विषयों के अवलोकन के साथ संयुक्त रूप से सामान्य प्रबंधन के तहत विषयों और सिद्धांतों से गुजरना पड़ता है। हालांकि, दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में प्रबंधन की एक विशेष शाखा में विशेषज्ञता का प्रावधान है। प्रबंधन की प्रसिद्ध शाखाओं में विपणन, वित्त, मानव संसाधन आदि शामिल हैं। संचालन प्रबंधन के लिए आपको निम्नलिखित कौशल की आवश्यकता होती है :

नेतृत्व
नीति, योजना और रणनीति की समझ
नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने, लागू करने और समीक्षा करने की क्षमता
बजट, रिपोर्टिंग, योजना और लेखा परीक्षा की देखरेख करने की क्षमता
आवश्यक कानूनी और नियामक दस्तावेजों की समझ
इसके साथ-साथ आपको इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है :
सुनिश्चित करें कि आप सही मेट्रिक्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं
मुख्य समस्याओं को पहचानने के लिए हमेशा डेटा का उपयोग करें

नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ अप-टू-डेट रहने में विश्वास करें
स्वचालन से पहले प्रक्रियाओं पर ध्यान दें
ध्यान से लोगों के साथ कम्यूनिकेट करें

ऑपरेशन्स मैनेजर बनने के लिए आवश्यकता योग्यता
संचालन प्रबंधन के संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की डिग्री के साथ, छात्रों को ज्ञान और विपणन योग्य कौशल विकसित करना होता है, जिसे वे अपने कॅरियर के दौरान बना सकते हैं। इसके अलावा, एक संचालन प्रबंधक होने के लिए, किसी के पास मजबूत नेतृत्व और पारस्परिक कौशल, शानदार संचार और ग्राहक की आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। संचालन प्रबंधक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है -
विषय संयोजन - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम उम्मीदवारों के पास 10 + 2 + 3 प्रणाली के माध्यम से योग्यता और किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी



चाहिए
उम्मीदवारों के पास ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में एमबीए (ऑपरेशन्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशन्स मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री का भी बहुत महत्त्व होता है

ऑपरेशन्स मैनेजर के जॉब रोलस
सप्लाइ चेन मैनेजर
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर
प्लांट मैनेजर
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर
परचेस मैनेजर
फैसिलिटी मैनेजर
इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजर

रोजगार के अवसर
एक ऑपरेशन्स मैनेजर के रूप में इस क्षेत्र में कॅरियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर होते हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में संचालन प्रबंधकों के लिए बहुत स्कोप है। कुछ शीर्ष क्षेत्र इस प्रकार हैं :

स्वास्थ्य कॉर्पोरेट व्यवसाय
बहुराष्ट्रीय कंपनियां
हॉस्पिटैलिटी
विनिर्माण और खुदरा
वित्तीय संस्थाएं
बीमा क्षेत्र
सूचना प्रौद्योगिकी
ई-कॉमर्स
वेयरहाउसिंग
निर्माण
सलाहकारी फर्म

सूडान में फंसे कर्नाटक के 31 आदिवासी, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

बेंगलुरु। सूडान में शीर्ष दो जनरल के प्रति वफादार सैन्य बलों की लड़ाई में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं। देश में लगातार तीसरे दिन भी सेना और शक्तिशाली बल के बीच संघर्ष जारी है। वहीं कर्नाटक के कम से कम 31 आदिवासी सूडान शहर अल फ़शेर में फंसे हुए हैं। 31 लोग हकी पिक्की जनजाति के हैं, जो एक अर्ध-खानाबदोश आदिवासी समूह है। इस सप्ताह के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद से उनके पास पर्याप्त खाद्य आपूर्ति नहीं है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि विदेश मंत्रालय को सूडान में आदिवासियों की स्थिति के बारे में सूचित किया है और फंसे हुए लोगों से बाहर नहीं निकलने और देश में भारतीय दूतावास के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को कर्नाटका विरोधी करार देकर दावा किया कि वे सूडान में आदिवासियों को बचाने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं।

लंदन में तिरंगे का अपमान, जांच करेगी एनआईए

नई दिल्ली। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। सूत्रों ने कहा कि एनआईए पिछले महीने लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानी समर्थक विरोध प्रदर्शन की जांच करेगी। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एनआईए को जांच की अनुमति दी है। प्रदर्शन मामले में पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इन्फोर्मुट मिले हैं। मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एनआईए ने केस टेकओवर कर लिया है। एनआईए सूत्रों के अनुसार मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सहित खालिस्तानी आतंकीयों की भूमिका देखने को मिली है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मामले में जांच को हरी झंडी मिली है। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से खालिस्तानी और उनके समर्थकों के खिलाफ 24 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। लंदन में पूर्व के मिशन में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों को लेकर गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार से बात की है। विवरण के अनुसार, 5वें भारत-ब्रिटेन गृह मामलों के संवाद के दौरान दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच खालिस्तानी गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में आयोजित संवाद का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव, अजय कुमार भल्ल ने किया, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्थायी सचिव, गृह कार्यालय, सर मैथ्यू रायक्रॉफ्ट ने किया।

मुख्यमंत्री योगी को जान से मरने की धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज किया

बागपत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी संबंधी पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि विवेचना के आधार पर कार्रवाई होगी। उसके अनुसार प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी बागपत का रहने वाला नहीं है। पुलिस के मुताबिक अमन रजा नामक एक व्यक्ति ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी से संबंधित संदेश भेजा है। इस स्क्रीनशॉट को टैग कर टि्वटर अकाउंट नितिन तोमर द्वारा मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य अधिकारियों को ट्वीट किया गया। उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने मामले में कोतवाली में सूचना मुकदमा दर्ज कराया। बागपत पुलिस क्षेत्राधिकारी डी के शर्मा ने बताया कि अमन रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की विवेचना के आधार पर कार्रवाई होगी। उनके अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अमन रजा झारखंड का निवासी है।

छत्तीसगढ़ : सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, दो गिरफ्तार

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मंगलवार को एक नक्सली को मार गिराया तथा दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक आनंदेय वाण्यो ने बताया कि जिले के नैमड़ थाना क्षेत्र में कचलावारी गांव के जंगल में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया तथा दो नक्सलियों को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि नैमड़ थाना क्षेत्र में भरमादूर परिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रेडडी गांव स्थित थिचिर से डीआरजी के दल को गश्त पर रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि दल जब आज सुबह लगभग आठ बजे कचलावारी गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उनके अनुसार सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की तथा कुछ दूर तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी होने के बाद नक्सली वहां से भाग गए। वाण्यो ने बताया पुलिस और नक्सलियों की बीच मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को पकड़ लिया जबकि घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार एक नक्सली घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोविड-19 से संक्रमित हुए

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस्पताल और नागरिक उड्डयन मंत्री ने टि्वटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों में भरे सभों में आए लोगों से सावधानी बरतने और अपना कोविड परीक्षण कराने का अनुरोध करता हूँ। संक्रमण के कारण सिंधिया मंगलवार को मुंबई में इंडिया स्टील 2023 कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए।

पंजाब और दिल्ली पुलिस ने मोहाली में दी दबिश, भगोड़े अमृतपाल की मदद करने वाले दो साथी गिरफ्तार

नयी दिल्ली। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह के दो और करीबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के मोहाली के सेक्टर 89 से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में एक महिला भी है। बताया जाता है कि पुलिस ने जिन दो लोगों को हिरासत में लिया है उन पर अमृतपाल को भगाने में मदद करने का आरोप है। दोनों ने उसे संसाधन उपलब्ध कराए थे। पकड़े गए दो लोगों में से एक का नाम गुरजट सिंह और महिला का नाम निशा रानी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरजट सिंह अमृतपाल सिंह का काफी करीबी है। इससे पहले बीते दिनों कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के एक करीबी मोहल्लियों को यहां ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अमृतपाल सिंह को पनाह देने और अन्य सहायता प्रदान करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जोगा सिंह को रविवार को एक अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने कहा था कि लुधियाना निवासी और पीलीभीत में एक डेरा के प्रभारी जोगा सिंह को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से गिरफ्तार किया गया था, जब वह हरियाणा से पंजाब आया था। जोगा को अमृतसर पुलिस (ग्रामीण) और होशियारपुर पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा था कि जोगा अमृतपाल के सीधे संपर्क में था।

कांग्रेसी नेता को कुर्सी से बांधकर घसीटा

विदिशा। विदिशा जिले के सिरोंज में प्रतिष्ठित कांग्रेस नेता अशोक जैन खर्चा के साथ मारपीट करने और घसीट जाने की घटना का वीडियो वायरल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनवर खान, बोहराबाड़ी के मुस्लामी और उनके साथ एक हरी शर्ट वाले युवक ने अशोक जैन के साथ मारपीट की। उन्हें रस्सी से बांधकर घसीटा गया। इसी मारपीट के दौरान राकेश गोहिल नामक युवक भी पहुंचा, उसने भी अशोक के साथ मारपीट की। 60 वर्षीय कांग्रेस नेता ने वहां से छुट्टा, उसने भी अशोक के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले अशोक जैन खर्चा के साथ की गई मारपीट चर्चा का विषय बनी हुई है।

डबल इंजन सरकार ने यूपी का चित्र और चरित्र दोनों बदला: पीयूष गोयल

लखनऊ (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने यूपी का चित्र व चरित्र दोनों ही बदल दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के लिए कल्पना से बहुरंग कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान (पीएम मित्र) योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में एक हजार एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को लेकर आयोजित एमओयू के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में भेदभाव क्या होता है, उत्तर प्रदेश की जनता ठीक से जानती है। 2017 के पहले तक यूपी के लोगों ने इस भेदभाव को झेला है। आज जब डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है तो छह वर्षों में यूपी की बदली हुई तस्वीर हम सबके सामने है।

मंत्री ने कहा कि यूपी में बहुत सी सरकारें आईं और गईं, सबने अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम किया। कानून व्यवस्था



और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य में उद्योग लगाने की सबसे आवश्यक मांग है। उत्तर प्रदेश के विगत कुछ वर्षों में बहुत कार्य हुआ है। यही वजह है कि यूपी वन टूरिज्म डेवलपमेंट इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसा आयोजन कल्पना के बाहर था। देश और विदेश के निवेशक यूपी जो आइएस में होड़ लगाकर

खड़े थे। यूपी जैसी प्रतिभा और मेहनत देश किसी अन्य राज्य में नहीं है। आने वाले दिनों में विकास की दिशा और यहां के लोगों की दशा बदलने वाली है।

केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री विक्रम जरादेश ने कहा कि हैडलूम और हैडीक्राफ्ट एक हुनर है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विश्वकर्मा का दर्जा दिया गया है। इस हुनर से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

इससे जुड़कर देश और उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सीएम योगी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट का आधार यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना है। कार्यक्रम में अपर सचिव टेक्सटाइल, भारत सरकार रोहित कंसल और हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, एमएसएमई, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के बीच एमओयू हस्तांतरित हुआ। निजी निवेशकों में आदित्य बिड़ला ग्रुप, मेसर्स जीएसएल स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अजुम डेनिम कार्टों एलएनपी, मेसर्स अधिकांश टेक्सटाइल लिमिटेड, मेसर्स एसवीएम, मेसर्स जोसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एमएलके एक्सपोर्ट लिमिटेड और मेसर्स पाथ थ्रेड प्राइवेट लिमिटेड के बीच भी एमओयू हस्तांतरित हुए।

समलैंगिक विवाह पर सीजेआई... हम सब कुछ नहीं तय कर सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति एस आर भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की। इस बेहद मौलिक मुद्दा बताने हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सम्मेलन भेजा था।

इस दौरान वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्स ओरिएंटेशन सिर्फ महिला-पुरुष के बीच नहीं, बल्कि समान लिंग के बीच भी होता है। समलैंगिक समूहों की ओर से वकील रोहतगी ने कहा कि हमें सम्मान से जीने का अधिकार है और यह अधिकार संविधान में दिया है। हमें विवाह करने का अधिकार है और हमें राज्य सरकार से विवाह को मान्यता और अधिकार मिले। समलैंगिक विवाह पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सब कुछ नहीं तय कर सकते।

बता दें कि इसके पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका का उल्लेख करने वाले सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता के प्रतिवेदन का संज्ञान लिया।



केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं 'शहरी सभ्रतवादी विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं और विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए। केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाहों की कानूनी वैधता 'पर्सनल लॉ और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों के नाचुक संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी।

इस मामले को सुनवाई और फैसला देश पर व्यापक प्रभाव डालेगा, क्योंकि आम नागरिक और राजनीतिक दल इस विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं। दो समलैंगिक जोड़ों ने विवाह करने के उनके अधिकार के क्रियाव्यवन और विशेष विवाह कानून के तहत उनके विवाह के पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए, अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर न्यायालय ने पिछले साल 25 नवंबर को केंद्र से अपना जवाब देने को कहा था।

सीजेआई और सॉलिडिटर जनरल के बीच हुई तीखी नोकझोंक

समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र में टन गड़बड़ा जा रहा है। सुनवाई शुरू की, तब केंद्र ने आपत्ति जाहिर की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे याचिकाओं का दायरा समझना चाहते हैं। इस पर सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता केंद्र के प्रिप्लिमनरी सबमिशन का जवाब दें। सीजेआई ने कहा कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं डिसाइड करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को यह बताने नहीं दूंगा कि इस अदालत की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए। इस पर एसजी ने कहा कि फिर हमें यह सोचने दीजिए कि सरकार को इस सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए भी या नहीं। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सरकार का यह कहना कि वह सुनवाई में हिस्सा लेगी या नहीं, अच्छा नहीं लगता। यह बेहद अहम मामला है। इतनी बहस के बाद सुनवाई शुरू हुई।

यह शर्मनाक है, शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं लोग: पप्पू यादव

एनसीपी छोड़ने की अफवाहों को अजीत पवार ने सिर से नकारा

मुंबई (एजेंसी)। एनसीपी छोड़ने की अफवाहों को महाराष्ट्र विधायक अजीत पवार ने सिर से नकार दिया है। उन्होंने पार्टी नेता अनिल पाटिल से हुई मुलाकात के बाद कहा कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि विगत दो दिनों से ये खबरें जोर पकड़ रही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबरों पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा -मेरे बारे में फैली अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं एनसीपी के साथ हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा। एनसीपी नेता अजीत पवार के कथित रूप से बवाल अटकलों के बीच अजीत पवार से मुलाकात के बाद पार्टी नेता अनिल पाटिल ने कहा आज मैंने उस न्यूज के बारे में चर्चा की, जो 2-3 दिन से चल रही थी। जो न्यूज में चल रहा है वैसा कहीं पर चर्चा नहीं हुआ है। तो इसे रोकना चाहिए क्योंकि आज तक कोई चर्चा दादा बहन और सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया।

जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने मोतिहारी में पीड़ित परिजनों से की मुलाकात

जहरीली शराब आम लोगों के लिए बन गया नासूर

मोतिहारी (एजेंसी)। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मोतिहारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद सदर अस्पताल में इलाजित लोगों से मुलाकात करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान पप्पू यादव ने मीडिया से कहा कि जहरीली शराब आम लोगों की जिंदगी के लिए नासूर बन गया है। यह शर्मनाक है कि शराबबंदी वाले राज्य में लगातार लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि शराबबंदी अच्छे नियत से की गई थी, लेकिन

जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को जो 4 लाख रुपये का मुआवजा की बात हुई है, वह अविश्वसनीय है

समय पर उसकी समीक्षा किए बिना शराब से मौत की घटना के पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया गए, जहां दर्जनों लोग काल के गाल में समा गए। हमने उनके परिजनों से मुलाकात की और 10 परिवार को पार्टी की ओर से तत्काल 10-10 हजार रूप के आर्थिक मदद भी की। हम सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा बिहार में

जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को जो 4 लाख रुपये का मुआवजा की बात हुई है, वह अविश्वसनीय है। सस्ती और जहरीली शराब पीकर लोगों की जान जा रही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, शराब पर 70 प्रतिशत टैक्स लगा दीजिए और यह सुनिश्चित कर दीजिए कि शराब गांव और पंचायत में उपलब्ध न हो। साथ ही 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब न मिले, इसके लिए आधार कार्ड की सहायता ली जा सकती है। हम प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस पर विचार करें।

भाजपा को अपनी दूसरी मां मानते हैं और इसके खिलाफ नहीं जाएंगे : एसए रामदास

- टिकट कटने से भाजपा विधायक एसए रामदास नाराज भी दिखे

दिल्ली। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज कृष्णराज निर्वचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक एसए रामदास ने पार्टी सांसद प्रताप सिन्हा और चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार टीएस श्रीवत्स से मिलने से इनकार कर दिया। दोनों नेता सोमवार रात रामदास से मिलने उनके विद्यारण्यपुरा स्थित घर गए थे लेकिन निवर्तमान विधायक ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि वह भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। रामदास के अपनी ही पार्टी के साथियों से मिलने से इनकार करने की जानकारी मिलते ही राज्य की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गयी है। रामदास के समर्थक शनिवार को बड़ी संख्या में उनके आवास के सामने जमा हुए थे और उन्हें पार्टी से टिकट देने की मांग को लेकर नारे लगाए थे। वह ब्राह्मण और लिगावित बहुल कृष्णराज निर्वचन क्षेत्र से चार बार निर्वाचित हुए हैं। रामदास ने कहा कि कुछ दलों ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चार बार निर्वचन क्षेत्र से जीतने के बावजूद पार्टी ने उन्हें कोई बार कैबिनेट सीट के योग्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह भाजपा को अपनी दूसरी मां मानते हैं और इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाला है।

शराब घोटाले से तो मिली राहत, लेकिन केजरीवाल के सामने अभी दो और कानूनी मुश्किलें

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भले ही शराब घोटाले में थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन अभी दो और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केजरीवाल इन दिनों चोतरफा मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उन्हें एक साथ कई मुकदमों और पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रविवार को दिल्ली के शराब घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने उनसे 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की तो अब उन्हें गोवा से गुजरात तक कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना है। गोवा में जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो गुजरात में एक मानहानि केस में कोर्ट में पेशी होगी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है। लेकिन इंडी की चार्जशीट में कुछ जगहों पर उनका नाम लिया गया है। वहीं, सीबीआई का भी कहना है कि कुछ आरोपियों ने पूछताछ में उनका नाम लिया है और इसको लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी था। 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब केजरीवाल बहार निकले तो उन्होंने कहा कि एजेंसी ने उन्हें दोबारा नहीं

बुलाया है। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है। सूत्रों को मानें तो केजरीवाल की ओर से दर्ज कराए गए बयानों और अन्य आरोपियों के बयानों की जांच के बाद वह तय किया जाएगा कि केजरीवाल से आगे पूछताछ होगी या नहीं। फिलहाल सीबीआई वाली पहली मुश्किल तो उन्होंने पार कर ली है। पूछताछ के बाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहार आए केजरीवाल ने यह जताने की कोशिश की कि सबकुछ ठीक ठाक है। उनके लिए अग्रहण या परेशान होने वाली स्थिति नहीं है।

बता दें कि गोवा पुलिस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सार्वजनिक संघर्षियों पर अवैध रूप से पोस्टर चिपकाने के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 27 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। परमेश पुलिस के मुताबिक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) के तहत केजरीवाल को नॉटिस जारी किया है। इसके तहत पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है यदि उचित शिकायत या संदेह है कि उसने अपराध किया है।

यूपी से बिहार तक गर्मी के तीखे तेवर, पारा 45 पार, लू का अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में फिलहाल मौसम खतरनाक रूप से करवट ले रहा है। कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं आ रहे हैं। इधर मौसम विज्ञान विभाग के नए अलर्ट से लोग और परेशान होने वाले हैं। आईएमडी ने कम से कम नौ राज्यों में लू यानिकी हीटवेव की चेतावनी दी है। वहीं इन राज्यों के कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चार अन्य राज्यों- सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर

प्रदेश में हीट वेव की स्थिति होने की आशंका है। जो आने वाले समय में लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है। यहां यह बात गौरतलब है कि देश भर में सामान्य से अधिक गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों को मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने से कुछ राहत मिलेगी। पंजाब और हरियाणा में सोमवार को लू जैसा तापमान रहा, मंगलवार को भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। हीटवेव के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही चार अन्य राज्यों- सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर

तापमान से है, जो या तो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या भारी काम करते हैं। जानकारों का कहना है कि अलर्ट महाराष्ट्र सरकार के एक कार्यक्रम में कई घंटे खुले में बैठने के दौरान 13 लोगों की मौत के एक दिन बाद आया है। आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मुरुगुजय महापात्र ने कहा है कि जब हवाएं पूर्वी दिशा से या बंगाल की खाड़ी की दिशा से चलती हैं तो कई बार बादल छा जाते हैं जो पूर्वी राज्यों में तापमान को कम कर देते हैं। लेकिन उत्तर-पश्चिम से गर्म, शुष्क हवाएं पूर्वी भारत में चल रही हैं। इसलिए, पूर्वी राज्यों के लोगों को पर्याप्त रूप से गर्मी से बचाव के उपाय करने की आवश्यकता है।



नवसारी को एक साल में मिला दूसरा टाइडल रेगुलेटर डेम, मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

अब्रामा में 10 करोड़ स्मए की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास

अंबिका नदी पर डुबारुपुल के स्थान पर 39 करोड़ स्मए की लागत से नवनिर्मित ब्रिज का लोकार्पण

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले को एक वर्ष में दूसरा डेम मिला है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने मंगलवार को इसका शिलान्यास किया। दरअसल समुद्री भरती का पानी पूर्ण नदी के जरिए नवसारी के गांवों में खरापन बढ़ता है। इसकी रोकथाम के लिए कई सालों से पूर्ण नदी पर टाइडल रेगुलेटर डेम बनाने की मांग की जा रही थी। आज यह मांग पूरी हो गई है। नवसारी जिले के कस्बापार में 110 करोड़ स्मए की लागत से निर्मित 'पूर्ण टाइडल रेगुलेटर डेम प्रोजेक्ट' का मंगलवार को शिलान्यास करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विकास की इमारत पंचशक्ति के आधार पर रखी है, जिसके मोटे फल राज्य की जनता को मिल रहे हैं। पंचशक्ति अर्थात् जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति, रक्षा शक्ति तथा जन शक्ति के जरिये ही गुजरात विकास की राह में अग्रसर रहा है ऐसे में राज्य सरकार ने जल शक्ति का महिमागान करते हुए इसे जनशक्ति से जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में पीने के, घर में उपयोग करने के तथा सिंचाई के पानी की समस्या न हो; इसके लिए उदाहरणीय जल व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण टाइडल रेगुलेटर योजना की ई-तकती का अनावरण किया तथा प्रोजेक्ट स्थल पर भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री के करकमलों से चीखली में 38 करोड़ स्मए की लागत से बनने वाली 100 ब्रेड के सबडिस्ट्रिक्टहॉस्पिटल तथा जलालपुर तहसील के अब्रामा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ



गुजरात द्वारा 90 करोड़ की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। साथ ही गणदेवी-अमलसाड मार्ग पर धमडाछा के पास अंबिका नदी पर डुबारुपुल के स्थान पर राज्य



सड़क एवं भवन विभाग द्वारा 39 करोड़ स्मए की लागत से नवनिर्मित हाईलेवलब्रिज कालोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कस्बापार क्रिकेट ग्राउंड में नर्मदा, जल संसाधन, जलापूर्ति एवं कल्पसार विभाग द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित

आयामों से राज्य में भूजल स्तर ऊँचा है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण रेगुलेटर प्रोजेक्ट सेनवसारी शहर तथा आसपास के 21 गाँवों के लोगों को होने वाले आर्थिक लाभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से 18 किलोमीटर लंबा एक विशाल जलाशय बनेगा,

देगा। इससे सतही एवं भूमिगत जल की लवणता तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और यहाँ मीठे पानी का विशाल सरोवर बनने से आसपास की भूमि का भूमिगत जल स्तर ऊपर उठेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए

कहा कि पूर्ण नदी का जल नवसारी जिले के विकास का अमृत बनेगा। पटेलने पानी को विकास का मुख्य आधार बताते हुए कहा कि जलाशयों सहित भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाना सरकार का लक्ष्य है, ताकि राज्य में पेयजल या सिंचाई के पानी की समस्या न हो। बिलिमोर के पास कावेरी नदी पर एक साल पूर्व शुरू किया गया वाघरेच टाइडल रेगुलेटर प्रोजेक्ट समयबद्ध कार्य के कारण पूर्णता की ओर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की विशिष्ट कार्यप्रणाली 'जिन विकास कार्यों का शिलान्यास करें, उनका समयबद्ध लोकार्पण हो' से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने गौरवपूर्वक कहा कि वाघरेच टाइडल प्रोजेक्ट इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि हमारी सरकार के लिए कॉममिनेन केन्द्र में है। पूर्व में भी राज्य सरकार योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लगातार सजग रही है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जाति-धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिक धर्म के आधार पर हमेशा सुशासन देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक जिले में ७५ अमृत सरोवरों के निर्माण करने का रचनात्मक सुझाव दिया था, जिसका अनुसरण करते हुए भावी पीढ़ी को जल की समृद्ध विरासत देने के लक्ष्य के साथ प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण तेजी से हो रहा है।

मोरबी दुर्घटना ब्रिज बनाने वाली कंपनी में अंतरिम मुआवजे के तौर हाईकोर्ट में जमा किए 14.62 करोड़

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

मोरबी, पिछले साल दिवाली के बाद मोरबी में हुई ब्रिज दुर्घटना में 135 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिज दुर्घटना मामले की आज गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि ब्रिज बनाने वाली ओरेवा ग्रुप ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर कोर्ट में ₹ 14.62 करोड़ स्मए जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले

भी मोरबी ब्रिज की निर्माता कंपनी ने मुआवजे की रकम जमा करवाई थी और शेष रकम ₹ 14.62 करोड़ आज हाईकोर्ट में जमा करवा दी है। इसलिए फिलहाल मामले को पूर्ण विराम देना चाहिए। बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में बना केबल ब्रिज टूट गया था और उस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। कंपनी ने कार्यकारी चीफ जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच को

बताया कि उसने पीड़ितों को राहत के तौर पर भुगतान करने के लिए ₹ 14.62 करोड़ की रकम गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा कर दी है। जिसमें मुआवजे की समान रकम दो किशतों में जमा की गई है। ओरेवा ग्रुप ने गुजरात हाईकोर्ट में आज बताया कि फरवरी में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ब्रिज दुर्घटना के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर आज ₹ 14.62 करोड़ जमा करवाए गए हैं।

तांत्रिक विधि के नाम पर महिला से दुष्कर्म, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस की जांच शुरू

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

वडोदरा, शहर में एक महिला को ज़्यादा स्मए कमाने की लालच में तांत्रिक विधि कराना महंगा पड़ गया। तांत्रिक ने विधि के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद अपने साथ रख लिया। एक दिन महिला से झगड़ा कर तांत्रिक फरार हो गया। जिससे महिला ने वडोदरा पुलिस थाने में तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जानकारी के मुताबिक वडोदरा के गोली क्षेत्र में रहनेवाली एक महिला की पहले दो दफा शादी हो चुकी है। पहले पति से महिला को दो संतानें हुईं। पहले पति के विवाहेतर संबंधों के चलते महिला ने उसे छोड़ दूसरी शादी कर ली। दूसरा पति का शराब

का आदी था, इसलिए उसे भी छोड़ दिया। बाद में महिला का अपने पिता के मित्र के जरिए भावनगर के एक तांत्रिक कश्यप उर्फ बापु हसमुख रामानुज से संपर्क हुआ। तांत्रिक ने महिला को अच्छी नौकरी दिलाने और ब्यूटी पार्लर कराने की लालच दी और कहा कि उसके लिए विधि करानी होगी। विधि कराने के लिए तांत्रिक को महिला अपने धर्म के भाई के घर ले गईं। जहाँ तांत्रिक महिला को एक कमरे में ले गया और कहा कि विधि के लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। जब महिला ने विधि के लिए कपड़े उतारने की जख्त पर सवाल किया तो तांत्रिक ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके पश्चात तांत्रिक ने महिला से कहा कि अब हमारे

बीच संबंध कायम हो गए हैं यानी हमारी शादी हो गई है और हम पति-पत्नी बन गए हैं। मैं अपने माता-पिता से बात कर लूँ उसके बाद तुम्हें भावनगर आना होगा। इस घटना के बाद तांत्रिक ने महिला के साथ अनेकों बार दुष्कर्म किया और दोनों पति-पत्नी की तरह साथ में रहते थे। हालांकि बाद में तांत्रिक महिला को छोड़कर फरार हो गया। जिससे महिला ने वडोदरा के पुलिस थाने में तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद भी तांत्रिक शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहा था। जब मैंने इंकार कर दिया तो वह मुझे छोड़कर फरार हो गया।

भावनगर डमी कांड में विद्यार्थी नेता

युवराजसिंह जाड़ेजा को समन, बुधवार 12 बजे पेश हों

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

भावनगर डमी कांड में विद्यार्थी नेता युवराजसिंह को भावनगर पुलिस ने समन जारी कर बुधवार दोपहर 12 बजे तक पेश होने की ताकीद की है। युवराजसिंह जाड़ेजा को भावनगर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराना होगा। बता दें कि एक आरोपी बिपिन तिवेदी ने युवराजसिंह जाड़ेजा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने डमी कांड में छिपाने के लिए लाखों स्मए लिए हैं। वायरल हुए एक वीडियो में बिपिन

तिवेदी यह कहता नजर आ रहा है कि प्रदीप नामक व्यक्ति ने मुझसे कहा-युवराजसिंह बार बार मेरा नाम ले रहा है। जिसकी वजह से पुलिस मेरे घर आती है, ऐसा कहते हुए प्रदीप ने मुझसे युवराजसिंह के साथ बात करने को कहा था। जिसके बाद मैंने इस संदर्भ में युवराजसिंह से बातचीत की थी और बाद में प्रदीप, घनश्याम, शिवुभा तथा युवराजसिंह के बीच बैठक भी कराई थी। हालांकि दोपहर 2 बजे लेक्चर होने की वजह से मैं बैठक से निकल गया था। लेक्चर पूर्ण

होने के बाद मुझे पता चला कि ₹ 55 लाख में डील हो गई है। इस डील में युवराजसिंह के दो साले शिवुभा और कानभा भी शामिल थे।

55 लाख स्मए की हुई डील की रकम तीन किशतों में दी गई। हालांकि बिपिन तिवेदी के आरोपों को युवराजसिंह जाड़ेजा ने आधारहीन करार दिया था। इसी डमी कांड में मामले में भावनगर पुलिस ने पूछताछ के लिए युवराजसिंह को समन जारी कर बुधवार की दोपहर 12 बजे पहुंचने का आदेश दिया है।

सूरत की एक फर्म ने बनाई 50,907 हीरों से एक सिंगल रिंग

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुआ नाम

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

सूरत, हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स और इसकी समूह कंपनी एचके डिजाइन ने एक अंगूठी में अधिकतम संख्या में हीरे जड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है। सूरत की इस फर्म ने पिछले दिनों 50,907 हीरों से एक सिंगल रिंग बनाई थी। कंपनी को हाल ही में मुंबई में खिताब से सम्मानित किया गया था। इससे पहले भी सूरत की कई फर्म इस तरह की कोशिश करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स दर्ज करा चुकी हैं, हालांकि उसमें डायमंड की संख्या कम थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुई सिंगल रिंग (अंगूठी) की कीमत 65 लाख रुपये आंकी गई है।

50,907 डायमंड वाली अंगूठी को बनाने में नौ माह का समय लगा। इसमें डिजाइन से लेकर डायमंड की कटिंग और फिनिशिंग



का काम हुआ। इस रिंग के निर्माण में 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। रिंग में कुल आठ हिस्से हैं। इनमें पखुंडियों की परतें और टांग के साथ दो हीरे की डिस्क और तितली शामिल है। अंगूठी के प्रत्येक हीरे को कारीगरों की एक टीम द्वारा हाथ से सेट किया है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि इस अंगूठी का नाम यूटिएरिया रखा गया है।

जिसका मतलब प्रकृति के साथ एक हो जाना है। इस अंगूठी को बनाने का उद्देश्य प्रकृति के साथ इंसानों के संबंध को दिखाना है। एचके एक्सपोर्ट्स के संस्थापक और अध्यक्ष सावजी ढोलकिया के अनुसार हम पर्यावरण के संतुलन के रिंग में स्थापित प्रत्येक हीरे के लिए एक पेड़ लगाएंगे।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुई इस अंगूठी की खासियत यह है कि इस पूरी तरह से रिसाइकिल मेटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें रिसाइकिल गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल हुआ है। हरि कृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम इस रिंग को बनाने रिकार्ड 11 मार्च, 2023 को दर्ज किया गया है। कंपनी के एमडी घनश्याम घोलकिया के अनुसार हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के आभारी हैं, कि उन्होंने हमारी टीम की तरफ से कड़ी मेहनत के बाद तैयारी की गई।

राजकोट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन समेत 15 सदस्यों का इस्तीफा

क्रांति समय,सूरत

www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

राजकोट शहर की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजकोट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन समेत 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन ही गुजरात प्रदेश भाजपा कार्यालय कमलम में बैठक हुई थी और आज राजकोट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 15 सदस्यों के इस्तीफे के बाद राजनीति गरमा गई है। जानकारी के मुताबिक राजकोट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन अतुल पंडित, वाइस चेयरमैन संगीता छाया समेत 15 सदस्यों के आज कमलम में शहर प्रमुख कमलेश मिराणी और महापौर डॉ. प्रदीप डव की मौजूदगी में इस्तीफे ले

लिए गए। बताया जाता है कि पिछले काफी समय से राजकोट शहर भाजपा प्रमुख और शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच गुटबाजी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजकोट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन समेत 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के किसी प्रकार की गुटबंदी या आंतरिक कलह नहीं है। पार्टी के आदेश पर सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन अतुल पंडित, वाइस चेयरमैन संगीता छाया के अलावा किशोर परमार, विजय टोलिया, रवि गोहेल, किरिटी गोहेल, तेजस तिवेदी, जेडी भाखड़, शरद तलसाणिया, अश्विन दूधरेजिया, धैर्य पारेख, फाख बावाणी, पीना कोटक, जागृति भाणवाडिया और मेधावी सिंधव शामिल हैं।

उसे हम निष्ठापूर्वक निभाते हैं। आज नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्यों को इस्तीफा देने को कहा गया है और सभी ने दे भी दिया। पार्टी में किसी प्रकार की गुटबंदी या आंतरिक कलह नहीं है। पार्टी के आदेश पर सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन अतुल पंडित, वाइस चेयरमैन संगीता छाया के अलावा किशोर परमार, विजय टोलिया, रवि गोहेल, किरिटी गोहेल, तेजस तिवेदी, जेडी भाखड़, शरद तलसाणिया, अश्विन दूधरेजिया, धैर्य पारेख, फाख बावाणी, पीना कोटक, जागृति भाणवाडिया और मेधावी सिंधव शामिल हैं।